रजिस्ट्री सं० डी(डी)-73 REGISTERED No. D(D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13, 1976/कार्तिक 22, 1898
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13, 1976/KARTIKA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1976

का० आ० 4288.—लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनदीवी द्वीप (सिविल न्यायालय) विनियम, 1965 (1965 का 9) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1151, तारीख 19 मार्च, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी में क्रम संख्या 3 और उसके सामने स्तम्भ 1 और 2 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3. मुन्सिफों के न्यायालय:—

(क) मुन्सिफ न्यायालय, एन्ड्रोथ	केरल राज्य में कोज़ी कोडे, एन्ड्रोथ द्वीप, कलपेनी द्वीप, मिनिकोय द्वीप, कावारती द्वीप, जिनका मुख्यालय एन्ड्रोथ द्वीप होगा।
(ख) मुन्सिफ न्यायालय, अमिनि।	केरल राज्य में कोज़ी कोडे, अमिनि द्वीप, कडमट द्वीप, किल्टन द्वीप, चैटलेट द्वीप, वितरा द्वीप, और आगट्टी द्वीप, जिनका मुख्यालय अमिनि द्वीप होगा।

स्पष्टीकरण—(1) मुन्सिफ, केरल राज्य में कोज़ीकोडे में केवल उन्हीं सिविल वादों के विचारण के लिये न्यायालय लगा सकेंगे जिनमें दोनों पक्षकारों की ओर से वकील रखे जायें तथा जिनकी सुनवाई दोनों पक्षकार कोज़ी कोडे में कराना चाहें।

(2) मुन्सिफों को केरल राज्य में कोज़ी कोडे में अच्छे मौसम में दो मास के लिये ही न्यायालय लगाना अवश्यक होगा, इस संबंध में कार्यक्रम का समन्वय अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

(3) मुन्सिफों को मानसून की अवधि के दौरान केरल राज्य में कोज़ी कोडे में न्यायालय लगाना आवश्यक नहीं है।"

[फा० सं० 30/31/76-न्याय०]

प्रेम प्रसाद नय्यर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 25th October, 1976

S.O. 4288.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Civil Courts) Regulation, 1965 (9 of 1965), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 1154, dated the 19th March, 1969, namely :—

AMENDMENT

In the Table appended to the said notification for serial No. 3 and the entries against it in columns (1) and (2), the following shall be substituted, namely :—

"3. Courts of the Munsiffs :—

(a) Court of Munsiff, Androth.—Kozhikode in Kerala State, the Island of Androth, the Island of Kalpeni, the Island of Minicoy and the Island of Kavaratti, with headquarters at the Island of Androth.

(b) Court of Munsiff, Amini.—Kozhikode in Kerala State, the Island of Amini, the Island of Kadmat, the Island of Kiltan, the Island of Chellat, the Island of Bitra and the Island of Agatti with headquarters at the Island Amini.

Explanations.—(1) The Munsiffs may hold court at Kozhikode in Kerala State only for trial of civil suits in which both parties engage lawyers and desire it to be heard at Kozhikode.

(2) The Munsiffs need hold court at Kozhikode in Kerala State only for two months in fair season, the programme in this regard being co-ordinated by the Subordinate Judge.

(3) The Munsiffs need not hold court at Kozhikode in Kerala State during the monsoon period."

[No. 30/31/76-Jus.]

P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1976

आयकर

का० आ० 4289.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किय गया है:—

(1) मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभानी प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान (कृषि/पशुपालन/मीन उद्योग और औषध से भिन्न) के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त की गई राशि का पृथक लेखा रखेगा।

(2) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलापों की विवरणी प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूपों में देगा जो उस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

संस्थान

मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभानी।

यह अधिसूचना 7 जून, 1976 से प्रभावी है।

[सं० 1443(फा सं० 203/76/76 आ०क०अ० II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 17th August, 1976

INCOME-TAX

S.O. 4289.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, in the area of other natural or applied sciences subject to the following conditions :—

(1) That the Marathwada Agricultural University, Parbhani, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than Agricultural/Animal Husbandry/Fisheries & Medicine).

2. That the said university will furnish the annual Return of its Scientific Research Activities to the prescribed authority for every year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

The Marathwada Agricultural University, Parbhani.

This notification takes effect from 7th June, 1976.

[No. 1443 (F. No. 203/76/76-ITA. II)]

का० आ० 4290.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंण्ड (2) के प्रयोजनार्थ अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया है :—

(1) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों (कृषि/पशुपालन/मीन उद्योग और औषधि से भिन्न) के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त की गई राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान-सम्बन्धी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूपों में देगा जो इस प्रयोजनार्थ अधिकथित किए जाएं और उसे प्रज्ञापित किए जाएं।

संस्था

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद।

यह अधिसूचना 18 जून, 1976 से प्रभावी है।

[सं० 1444 (फा०सं० 203/90/76-आ का०आ II)]

S.O. 4290.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Secretary, Department of Science & Technology, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 in the area of other natural and applied sciences, subject to the following conditions :—

(i) That the Marathawada University, Aurangabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than Agricultural/Animal Husbandry/Fisheries & Medicine).

(ii) That the said University will furnish the Annual Return of its Scientific Research Activities to the prescribed authority for every year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

The Marathawada University, Aurangabad.

This notification takes effect from 18th June, 1976.

[No. 1444 (F. No. 203/90/76-ITA. II)]

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1976

का०आ० 4291.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंण्ड (3) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया है ।

(1) सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, इस छूट के अधीन उनके द्वारा संग्रहीत निधियों का पृथक् लेखा रखेगा;

(2) ऐसी निधियों का उपयोग केवल सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए किया जाएगा; और

(3) सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को वार्षिक रिपोर्ट देगा जिसमें इस छूट के अधीन संग्रहीत निधि और उसके उपयोग की रीति दर्शित की जाएगी ।

संस्था

सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 से प्रभावी है ।

[सं० 1461/फा० सं० 203/71/76-आ० क० अ०II]

New Delhi, the 31st August, 1976

S.O. 4291.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the fulfilment of the following conditions :—

(i) That the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, shall maintain separate accounts of the funds collected by them under the exemption ;

(ii) That such funds shall be utilised exclusively for promotion of research in Social Sciences; and

(iii) That the Institute of Constitutional & Parliamentary studies, New Delhi shall send an Annual Report to the Indian Council of Social Science Research New Delhi, showing the funds collected under the exemption and the manner in which the funds were utilised.

INSTITUTION

The Institute of Constitutional & Parliamentary Studies, New Delhi.

This notification takes effect from 1st April, 1976.

[No. 1461/F. No. 203/71/76-ITA. II]

का०आ० 4292.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंण्ड (2) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया है :—

(1) जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता, प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान (कृषि/पशुपालन/मीन उद्योग और औषध से भिन्न) के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजन के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(2) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अपने वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में देगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसको संसूचित किए जाएं

संस्था

जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

यह अधिसूचना 17 जून, 1976 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1462/फा० सं० 203/91/76-आ०क० अ०II]

S.O. 4292.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, in the area of other natural or applied science, subject to the following conditions :—

(i) that the Jadavpur University, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than Agriculture/Animal Husbandry/Fisheries & Medicines).

(ii) That the said University, will furnish the Annual return of its Scientific Research activities to the prescribed authority for every year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

The Jadavpur University, Calcutta.

This notification takes effect from 17th June, 1976.

[No. 1461/F. No. 203/91/76-ITA. II]

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1976

का० आ० 4293.—साधारण जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्थान को विहित प्राधिकारी, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंण्ड (2) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(1) कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि का पृथक लेखा रखेगा;

(2) कि उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलापों की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूपों में जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उन्हें प्रज्ञापित किए जाएं, प्रतिवर्ष 30 अप्रैल, तक विहित प्राधिकारी को देगा ।

संस्थान

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।

यह अधिसूचना 9, जुलाई, 1976 से प्रभावी है।

[सं० 1496/फा०सं० 203/108/76-आई० टी० ए०-II]

New Delhi, the 24th September, 1976

S.O. 4293.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 subject to the following conditions :—

(i) That the Guru Nanak Dev University, Amritsar, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said University, will furnish the annual return of its Scientific Research Activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

Guru Nanak Dev University, Amritsar.

This notification takes effect from 9th July, 1976.

[No. 1496/F. No. 203/108/76-ITA. II]

का०आ० 4294.—साधारण जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्थान को विहित प्राधिकारी, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (2) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(1) बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर (उड़ीसा) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि का पृथक लेखा रखेगा;

(2) उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलापों की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूपों में, जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उन्हें प्रज्ञापित किए जाएं, प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक विहित प्राधिकारी को देगा।

संस्थान

बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर, उड़ीसा।

यह अधिसूचना 16 जून, 1976 से प्रभावी है।

[सं० 1498/फा० सं० 203/106/76-आई०टी०ए० II]
टी० पी० झुनझुनवाला, निदेशक

S.O. 4294.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) That the Berhampur University, Berhampur (Orissa) will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research;

(ii) That the said University will furnish the annual return of its Scientific Research Activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

The Berhampur University, Berhampur (Orissa).

This notification takes effect from 16th June, 1976.

[No. 1498/F. No. 203/106/76-ITA. II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Director

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1976

का०आ० 4295.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री ओ० पी० सिन्हा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना सं० 1334 (फा०सं० 404/126/76-आई०टी०सी० सी०) तारीख 26-5-1976 के अधीन श्री शिव मोहन लाल की नियुक्ति श्री ओ० पी० सिन्हा के कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना श्री ओ० पी० सिन्हा के कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं० 1485 (फा०सं० 404/195/76-आई टी सी सी)]

New Delhi, the 15th September, 1976

S.O. 4295.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri O. P. Sinha, who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri Sheo Mohan Lal under Notification No. 1334 (F. No. 404/126/76-ITCC) dated 26-5-1976 shall be cancelled with effect from the date Shri O. P. Sinha takes over charge as Tax Recovery Officer.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri O. P. Sinha takes over charge as a Tax Recovery Officer.

[No. 1485 (F. No. 404/195/76-ITCC)]

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1976

का०आ० 4296.—अधिसूचना सं० 1157 (फा०सं० 404/95/75 आई टी सी सी) तारीख 25-11-1975 के अधीन श्री जे० एन० प्रसाद को, कर-वसूल, अधिकारी के रूप में की गई नियुक्ति रद्द की जाती है।

2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिसको वह कर वसूली अधिकारी का कार्यभार सौंप दें।

[सं० 1489 (फा०सं० 404/7/76 आई टी सी सी)]
बी० पी० मिसल, उप सचिव

New Delhi, the 16th September, 1976

S.O. 4296.—The appointment of Shri J. N. Prasad as Tax Recovery Officer made under Notification No. 1157 (F. No. 404/95/75-ITCC) dated 25-11-1975 is hereby cancelled.

2. This Notification shall come into force with effect from the date he hands over charge of Tax Recovery Officer.

[No. 1489 (F. No. 404/7/76-ITCC)]
V. P. MITTAL Dy. Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4297.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (छटा संशोधन) नियम, 1974 से संबंधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की अधिसूचना सं० 1(3)-संस्था V(ख)/74 तारीख 30 सितम्बर, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, नियम 1 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) ये 30 सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है ताकि उक्त अधिसूचना का लाभ उन मामलों में दिया जा सके जो 30 सितम्बर, 1974 अर्थात् अधिसूचना की तारीख को अथवा उसके पश्चात्, किन्तु राजपत्र में उसके प्रकाशन से पूर्व घटित हुए हैं।

इन नियमों के भूतलक्षी रूप से लागू किए जाने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

[सं० 1(3)-संस्था V(ख)/74]
एस०एस०एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 30th October, 1976

S.O. 4297.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. F. 1(3)-EV(B)/74 dated the 30th September, 1974 relating to the Central Civil Services (Pension) (Sixth Amendment) Rules, 1974, namely :—

In the said notification for sub-rule (2) of rule 1 the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) They shall be deemed to have come into force on the 30th September, 1974".

EXPLANATORY MEMORANDUM

Retrospective effect to this Notification is being given in order to allow the benefit of the aforesaid Notification in those cases which occurred on or after 30th September, 1974, i.e. the date of the Notification but before its publication in the Official Gazette.

The interest of no one is adversely affected by retrospective application of these rules.

[No. 1(3)-EV(B)/74]
S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1976

आयकर

का० आ० 4298.—केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 [फा०सं० 187/2/74-आई टी (ए० I)] तारीख 20-7-1974 और सं० 862 [फा०सं० 187/2/74-आई० टी० (ए० I)] तारीख 26-3-75 और सं० 1031 तारीख 12-8-75 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

अनुसूची

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
19 पुणे-I	पुणे	1 क—वार्ड पुणे, ख—वार्ड पुणे, ग—वार्ड पुणे, ङ—वार्ड पुणे, छ—वार्ड पुणे, ड—वार्ड पुणे, ढ—वार्ड पुणे, व—वार्ड पुणे, ध—वार्ड पुणे, ब—वार्ड पुणे, भ—वार्ड पुणे, एस एस सी-I, पुणे कामर्शियल सर्किल-I पुणे और कामर्शियल सर्किल-II पुणे 2 अहमद नगर 3 बारसी 4 इचलकरन्जी 5 कोलाबा 6 कोल्हापुर 7 रत्नागिरि 8 सांगली 9 सतारा 10 शोलापुर
19क पुणे-II	पुणे	1 घ—वार्ड, पुणे, च—वार्ड पुणे, ज—वार्ड पुणे, ल—वार्ड पुणे, ट—वार्ड पुणे, ठ—वार्ड पुणे, त—वार्ड पुणे, थ—वार्ड पुणे, न—वार्ड पुणे, प—वार्ड पुणे, जी०एच०क्यू० सर्किल-I पुणे, जी०एच०क्यू० सर्किल-II पुणे, जी०एच०क्यू०, सर्किल-III पुणे एस०एण्ड आर० सर्किल-IV पुणे, और एम० एस० सी०-II पुणे। 2 धूलिया 3 जलगांव 4 मालेगांव 5 नासिक 6 पालघर 7 थाना।

यह अधिसूचना 21-8-1976 से प्रभावी है।

[सं० 1445/फा०सं० 191/30/76-आई टी (ए I)]
एम० शास्त्री, अवर सचिव

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 20th August, 1976

INCOME TAX

S. O. 4298:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its Notification No. 679 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dated 20-7-1974 and No. 862 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dated 26-3-1975 and No. 1031 dated 12-8-1975 as amended from time to time.

SCHEDULE

Commissioner of Income-Tax	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
19. Poona-I	Poona	1. A—Ward, Poona, B—Ward, Poona, C—Ward, Poona, E—Ward, Poona, G—Ward, Poona, M—Ward, Poona, N—Ward, Poona, R—Ward, Poona, S—Ward, Poona, W—Ward, Poona, X—Ward, Poona, SSC-I, Poona, Com. Circle—I, Poona and Com. Circle—II, Poona. 2. Ahmednagar. 3. Barsi. 4. Ichalkaranji. 5. Kolaba. 6. Kolhapur. 7. Ratnagiri 8. Sangli. 9. Satara. 10. Sholapur.
19A. Poona-II.	Poona	1. D—Ward, Poona, F—Ward. Poona, H—Ward, Poona, J—Ward, Poona, K—Ward, Poona, L—Ward, Poona, P—Ward, Poona, Q—Ward, Poona, T—Ward, Poona, U—Ward, Poona, G.H.Q., Circle—I, Poona, G.H.Q., Circle-II, Poona, G.H.Q. Circle-III, Poona, S&R Circle—IV, Poona and SSC-II, Poona 2. Dhulia. 3. Jalgaon. 4. Malegaon. 5. Nasik. 6. Palghar. 7. Thana.

This Notification shall take effect from 21-8-1976.

[No. 1445/F. No. 191/30/76-IT (AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1976

का०आ० 4299.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड द्वारा प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और प्रबन्ध परामर्श के क्षेत्र में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

संस्था

केमिकल एण्ड मेटालर्जिकल डिजायन कंपनी प्रा० लि०, नई दिल्ली यह अनुमोदन 1 अप्रैल 1971 से प्रभावी है

[सं० 1478/फा० सं० 203/84/75 आ० क० आ०-II]

टी० पी० झुनझुनवाला, सचिव

New Delhi, the 13th September, 1976

S.O. 4299.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of section 35D of the Income-tax Act, 1961 in the fields of Technological, Engineering & Management Consultancy.

INSTITUTION

Chemical and Metallurgical Design Company Pvt. Ltd., New Delhi.

The approval takes effect from 1st April, 1971.

[No. 1478/F. No. 203/84/75-ITA. II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Secy.

समाहर्ता कार्यालय, दिल्ली

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1976

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

का०आ० 4300.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अंतर्गत मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा, संलग्न विवरण के स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद के और उससे ऊपर के पद के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों को यह अधिकार देता हूं कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, विवरण के स्तम्भ 5 में दी गई परिसीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, स्तम्भ 3 में बताये गये नियमों के उपबंधों द्वारा दी गई समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करें। नीचे उल्लिखित समाहर्ता कार्यालय की अधिसूचनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनके द्वारा शक्तियां सौंपी गयी हैं।

1. अधिसूचना संख्या 4(8) 2 सी ई/60 दिनांक 30-12-62
2. अधिसूचना सं० 9/62 दिनांक 22-1-63
3. अधिसूचना सं० 6/67 दिनांक 1-9-67
4. अधिसूचना सं० 3/69 दिनांक 19-7-69
5. अधिसूचना सं० 3/73 दिनांक 22-9-73
6. अधिसूचना सं० 2/74 दिनांक 20-7-74

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क योग्य विभिन्न वस्तुओं की बाबत विशेष कार्यविधि के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को समाहर्ता की शक्तियों के प्रस्तावित प्रत्यायोजन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	समाहर्ता में निहित शक्तियों का प्रकार	नियम संख्या	उस अधिकारी का पद जिसे शक्तियां सौंपी जानी हैं	सीमाएं यदि कोई हों	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
I.	खण्डसारी चीनी :				
1.	विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति देने के लिए पहला ए०एस०पी० (विशेष कार्यविधि का आवेदन) स्वीकार करना ।	92क (1)	अधीक्षक		
2.	जिस अवधि के लिए अनुमति दी गई है उसके दौरान यदि कोई विनिर्माता ऐसी कार्य विधि का फायदा उठाने में असमर्थ रहे तो उसको माफ करना और यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए ।	92क (3)	सहायक समाहर्ता		
3.	(क) फार्म ए० एस०पी० में नवीकरण आवेदन स्वीकार करना ।	92क (4)	अधीक्षक		
	(ख) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का आवेदन करने में असमर्थ रहे तो उसको माफ करना और यह निश्चित करना कि विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से उसे किस अवधि तक रोका जाए ।	92क (4)	अधीक्षक सहायक समाहर्ता	15 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना	
4.	शुल्क देयता की गणना करने के प्रयोजन के लिए यूनिट के बंद रहने की अवधि को छोड़ देना ।	92ख स्पष्टीकरण (ग)	सहायक समाहर्ता	15 दिन से अधिक विलंब को माफ करना ।	
5.	सात दिन से कम अवधि तक विनिर्माण प्रक्रिया आरंभ करने या बंद करने की सूचना स्वीकार करना।	92ख (3)	अधीक्षक		
6.	उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म ए०आर० 8 में आवेदन करने या साप्ताहिक जमा कराने की असमर्थता को माफ करना ।	92ग (2)	अधीक्षक सहायक समाहर्ता	2 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना	
7.	किसी विनिर्माता को विशेष कार्यविधि का फायदा उठाने से रोकना ।	92क (खंड III)	सहायक समाहर्ता	2 दिन से अधिक के विलंब को माफ करना ।	
8.	ऐसे विनिर्माता के संबंध में जो विशेष कार्यविधि का फायदा उठाने में, या नियमों में दी गई कोई शर्त पूरी करने में असमर्थ रहे, इस कार्यविधि के उपबंधों को लागू करने की बाबत संपूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग करना ।	92च	*उप समाहर्ता		*जहां कोई उपसमाहर्ता नहीं है, समाहर्ता को खुद ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ।
II.	शक्ति चालित करघों पर उत्पादित सूती कपड़े और रेशमी कपड़े :				
1.	विशेष कार्यविधि के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति देने के लिए पहला ए० एस० पी० (विशेष कार्यविधि का आवेदन) स्वीकार करना ।	96झ (1)	अधीक्षक		
2.	निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए पहला ए० एस० पी० (विशेष कार्यविधि का आवेदन) स्वीकार करना ।	96झ (2)	सहायक समाहर्ता		
3.	जिस अवधि के लिए अनुमति दी गई है उसके दौरान यदि कोई विनिर्माता विशेष कार्यविधि का फायदा उठाने में असमर्थ रहे तो उसको माफ करना और/या यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक विशेष कार्यविधि के अंतर्गत कार्य करने से रोका जाए ।	96झ (3)	सहायक समाहर्ता		

1	2	3	4	5	6
4.	(क) फार्म ए० एस० पी० (विशेष कार्यविधि के आवेदन पत्र) में नवीकरण आवेदन स्वीकार करना।	96ब (4)	अधीक्षक		
	(ख) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का आवेदन करने में असमर्थ रहे तो उसको माफकरना और । या यह निश्चित करना कि उसे विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से किस अवधि तक रोका जाए।	96ब (4)	अधीक्षक	15 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना।	
			सहायक समाहर्ता	15 दिन से अधिक विलंब को माफ करना।	
5.	उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म ए०आर० 6 में आवेदन करने या तिमाही/सालाना जमा कराने की असमर्थता को माफ करना।	96ट (2)	अधीक्षक	तिमाही आवेदन पत्रों और तिमाही जमाओं के संबंध में 2 दिन से अनधिक विलंब और सालाना आवेदन पत्रों और सालाना जमाओं के संबंध में 10 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना।	
6.	जो कारखाने बंद किये गये थे और अब उत्पादन शुरू कर रहे हैं, उन्हें विशेष कार्यविधि का लाभ उठाने की अनुमति देना।	96 ठ	सहायक समाहर्ता	ऊपर दी गई सीमाओं से अधिक विलंब को माफ करना।	
7.	किसी विनिर्माता की आदत विशेष कार्यविधि के उपबंधों को लागू करने के लिए समस्त विवेकाधिकार का प्रयोग करना।	96 डडड	सहायक समाहर्ता *उप समाहर्ता		*जहां कोई उप समाहर्ता नहीं हैं वहां समाहर्ता को खुद ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।
III.	सूती धागा, ऊनी धागा और मद संख्या 18ब के अंतर्गत आने वाला धागा :				
1.	विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन पत्र (ए० एस० पी०) स्वीकार करना।	96फ (1)	अधीक्षक		
2.	निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन पत्र (ए० एस० पी०) स्वीकार करना।	96फ (2)	सहायक समाहर्ता		
3.	यदि कोई विनिर्माता विशेष कार्यविधि को छोड़ देने की सूचना समय पर देने में असमर्थ रहे तो उसे माफ करना और/या यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए।	96फ (3)	सहायक समाहर्ता		
4.	ऐसे विनिर्माता के संबंध में जो विशेष कार्यविधि का लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त पूरी करने में असमर्थ रहे, विशेष कार्यविधि के उपबंधों को लागू करने की आदत समस्त विवेकाधिकार का प्रयोग करना।	96 भ	*उप समाहर्ता		*जहां कोई उप समाहर्ता नहीं है वहां समाहर्ता को खुद ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।
IV	विद्युत बैटरी के भाग :				
1.	विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन (ए० एस० पी०) स्वीकार करना।	96म (1)	अधीक्षक		
2.	निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन स्वीकार करना।	96म (2)	अधीक्षक		
3.	ऐसे विनिर्माता के संबंध में, जो विशेष कार्यविधि के लिए अनुमति प्राप्त अवधि के दौरान इस कार्यविधि का लाभ उठाने में असमर्थ रहे, यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक इस कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए।	96म (3)	सहायक समाहर्ता		

1	2	3	4	5	6
4.	(क) विशेष कार्यविधि के आवेदन पत्रमें नवीकरण का आवेदन स्वीकार करना ।	96म (4)	अधीक्षक		
	(ख) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का आवेदन करने में असमर्थ रहे तो उसे माफी देना और/या यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए ।	96म (4)	अधीक्षक सहायक समाहर्ता	15 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना । 15 दिन से अधिक विलंब को माफ करना ।	
5.	उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म ए०आर० 9 में आवेदन करने या महावार जमा कराने की असमर्थता को माफ करना ।	96य (2)	अधीक्षक सहायक समाहर्ता	5 दिनों से अनधिक विलंब को माफ करना । 5 दिनों से अधिक विलंब को माफ करना ।	
6.	ऐसे विनिर्माता के संबंध में, जो विशेष कार्यविधि का लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त पूरी करने में असमर्थ रहे, विशेष कार्यविधि के उपबंधों को लागू करने के लिए समस्त विवेकाधिकार का प्रयोग करना ।	96ययययय*	उप समाहर्ता		*जहां कोई उप समाहर्ता नहीं है वहां समाहर्ता को इस शक्ति का खुद ही प्रयोग करना चाहिए ।
V	प्लाईवुड :				
1.	विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन (ए०एस.पी०) स्वीकार करना ।	96यक (1)	अधीक्षक		
2.	निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन (ए०एस०पी०) स्वीकार करना ।	96यक (2)	अधीक्षक		
3	ऐसे विनिर्माता के संबंध में जो विशेष कार्यविधि के लिए अनुमति प्राप्त अवधि के दौरान इस कार्यविधि का लाभ उठाने में असमर्थ रहे, यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक इस कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए ।	96यक (3)	सहायक समाहर्ता		
4.	(क) विशेष कार्यविधि के पहले आवेदन पत्र (ए० (ए०एस०पी०) में नवीकरण का आवेदन स्वीकार करना ।	96यक (4)	अधीक्षक		
	(ख) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का आवेदन करने में असमर्थ रहे तो उसे माफ करना और/या यह निश्चित करना कि उसे विशेष कार्यविधि के अंतर्गत कार्य करने से किस अवधि तक रोका जाए ।	96यक (4)	अधीक्षक सहायक समाहर्ता	15 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना 15 दिन से अधिक विलंब को माफ करना	
5.	उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म ए०आर० 10 में आवेदन करने की माहवार या जमा कराने की असमर्थता को माफ करना ।	96यघ (2)	अधीक्षक सहायक अभिकर्ता	5 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना । 5 दिन से अधिक विलंब को माफ करना ।	
6.	ऐसे विनिर्माता के संबंध में जो विशेष कार्यविधि का लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त पूरी करने में असमर्थ रहे, विशेष कार्यविधि के उपबंधों को लागू करने के लिए समस्त विवेकाधिकार का प्रयोग करना ।	96यछ	*उप समाहर्ता		*जहां कोई उप समाहर्ता नहीं है वहां समाहर्ता को खुद ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ।
VI	कपड़े के टुकड़े, पट्टी या मोटिफ पर किया गया कढ़ाई का काम :				
1.	विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन (ए०एस०पी०) स्वीकार करना ।	96यज (1)	अधीक्षक		

1	2	3	4	5	6
2.	निर्धारित अवधि के कम अवधि के लिए विशेष कार्य-विधि का पहला आवेदन पत्र ।	96 यज (2)	सहायक समाहर्ता		
3.	(ए०एस०पी०) स्वीकार करना ।				
3.	(क) विशेष कार्यविधि के आवेदन पत्र में नवीकरण आवेदन स्वीकार करना ।	96 यज (4)	अधीक्षक		
	(ख) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का आवेदन करने में असमर्थ रहे तो उसे माफी देना और/या यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए ।	96 यज (4)	अधीक्षक सहायक समाहर्ता	10 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना । 10 दिन से अधिक विलंब को माफ करना ।	
4.	सम्मिलित शुल्क उद्ग्रहण समय पर या निर्धारित प्रकार से अदा करने में कोई असमर्थ रहे तो सामान्य दर पर शुल्क अदा करने का दायित्व माफ करना ।	96 यझ (4)	सहायक समाहर्ता		
5.	ऐसे विनिर्माता के संबंध में, जो विशेष कार्यविधि का लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त पूरी करने में असमर्थ रहे, विशेष कार्यविधि के उपबंधों को लागू करने के लिए समस्त विवेकाधिकार का प्रयोग करना ।	96यड	*उप समाहर्ता		*जहां कोई उप समाहर्ता नहीं है वहां समाहर्ता को खुद ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ।
VII	भाप या शक्ति की सहायता के बिना संसाधित सूती कपड़े :				
1.	विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन (ए०एस.पी०) स्वीकार करना ।	96 यण (1)	अधीक्षक		
2.	निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए विशेष कार्यविधि का पहला आवेदन (ए०एस०पी०) स्वीकार करना ।	96यण (2)	अधीक्षक		
3.	यदि कोई विनिर्माता, अनुमति प्राप्त अवधि के दौरान विशेष कार्यविधि का लाभ न उठाने की उचित सूचना देने में असमर्थ रहे तो यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक विशेष कार्य विधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए ।	96 यण (3)	सहायक समाहर्ता		
4.	(क) विशेष कार्यविधि के आवेदन-पत्र में नवीकरन का आवेदन स्वीकार करना ।	96 यण (4)	अधीक्षक		
	(ख) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का आवेदन करने में असमर्थ रहे तो उसे माफ करना और/या यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए ।	96 यण (4)	अधीक्षक सहायक समाहर्ता	15 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना 15 दिन से अधिक विलंब को माफ करना ।	
5.	उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म ए०आर० 11 में आवेदन करने या माहवार जमा कराने की असमर्थता को माफ करना ।	96 यय (2)	अधीक्षक सहायक समाहर्ता	5 दिन से अनधिक विलंब को माफ करना । 5 दिन से अधिक विलंब को माफ करना ।	
6.	ऐसे विनिर्माता के संबंध में, जो विशेष कार्यविधि का लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त पूरी करने में असमर्थ रहे, विशेष कार्यविधि के उपबंधों को लागू करने के लिए समस्त विवेकाधिकार का प्रयोग करना ।	96 यय	*उप समाहर्ता		*जहां कोई उप समाहर्ता नहीं है वहां समाहर्ता को खुद ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ।

[अधिसूचना सं० 2/76 (सी सं० 4(8)/1 सी ई/73]

म० ला० अधिकार, समाहर्ता

(Central Excise Collectorate, Delhi)

New Delhi, the 19th August, 1976

(Central Excise)

S.O. 4300:—In exercise of the powers vested on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the Central Excise Officers of and above the rank specified in Column 4 of the enclosed statement, to exercise within their respective jurisdiction, the powers of Collector conferred by the provisions of Rules in Column 3 subject to the limitations, if any, set out in Column 5 of the statement. Attention is also drawn to following Notifications of the Collectorate delegating the powers.

Notification C. No. IV(8) 2CE/60 dt. 30-12-62.
(ii) Notf. 9/62 dt. 22-1-63.
(iii) Notf. 6/67 dt. 1-9-67.
(iv) Notf. 3/69 dt. 19-7-69.
(v) Notf. 3/73 dt. 22-9-73.
(vi) Notf. No. 2/74 dt. 20-7-74.

Statement showing the proposed delegation of collector's powers under the Central Excise Rules, 1944 Relating to special procedures in respect of various excisable commodities to subordinate officer.

Sl. No.	Nature of powers conferred on Collector	Rule No.	Rank of Officer to whom powers to be delegated	Limitations if any	Remarks
1	2	3	4	5	6
I.	Khandsari Sugar :				
1.	To accept first A.S.P. for grant of permission to work under the Special Procedure.	92A(1)	Superintendent		
2.	To condone and/or determine the period of preclusion from working under the Special Procedure in respect of a manufacturer who fails to avail of such procedure during the period for which permission has been granted.	92A(3)	Asstt. Collector		
3.	(a) To accept renewal application in form A.S.P.	92A(4)	Superintendent		
	(b) To condone and/or to determine the period of preclusion from working under the Spl. Procedure in respect of a manufacturer who fails to make an application for renewal.	92A(4)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delay not exceeding 15 days. For condoning delays exceeding 15 days.	
4.	To exclude the period of closure of unit for purposes of computing the duty liability.	92B (Explanation (c))	Asstt. Collector		
5.	To accept notice for commencing or closing manufacturing operation of a period shorter than seven days.	92B(3)	Superintendent		
6.	To condone failure to make application for removal of excisable goods in form A.R. 8 or to make the weekly deposits.	92C(2)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 2 days. For condoning delays exceeding 2 days.	
7.	To debar a manufacturer from availing of the special Procedure.	92E (Clause III)	Asstt. Collector.		
8.	To exercise overall discretionary powers to apply the provisions of Special Procedure to a manufacturer who has failed to avail himself of the procedure, or to comply with any conditions laid down in rules.	92F	*Deputy Collector		*Where there is no Dy. Collector, the power is to be exercised by Collector himself.
II.	Cotton fabrics and silk fabrics produced on power looms :				
1.	To accept first A.S.P. for grant of premisesion to work under the Special Procedure.	96I(1)	Superintendent		
2.	To accept first A.S.P. for a period less than the prescribed period.	96I(2)	Asstt. Collector		
3.	To determine the period for which a manufacturer may be precluded from working under the Special Procedure for failure to avail of such procedure during the period for which permission has been granted to him.	96I(3)	Asstt. Collector.		
4.	(a) To accept renewal application in form; A.S.P.	96I(4)	Superintendent		

2	3	4	5	6
(b) To condone and/or to determine the period of preclusion from working under the Special Procedure in respect of a manufacturer who fails to make an application for renewal.	96 I (4)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 15 days. For condoning delays exceeding 15 days.	
5. To condone failure to make application for removal of excisable goods in form A.R. 6 or to make quarterly/ annual deposits.	96K(2)	Superintendent	For condoning delays not exceeding 2 days in the case quarterly applications & quarterly deposits & delays not exceeding 10 days in the case of annual applications & annual depotits.	
		Asstt. Collector	For condoning delays exceeding the above.	
6. To grant permission to avail Special Procedure for closed factories resuming production.	96MM	Asstt. Collector		
7. To exercise overall discretionary powers to apply the provisions of Special Procedure to a manufacturer.	96MMMM	*Dy. Collector		*Where there is no Dy. Collector, the power is to be exercised by Collector himself.
III. Cotton yarn, woollen yarn & yarn falling under item No. 18E :				
1. To accept first A.S.P. for grant of permission to work under the Special Procedure.	96V(1)	Superintendent		
2. To accept first A.S.P. for a period shorter than the prescribed period.	96V(2)	Asstt. Collector		
3. To condone and/or determine the period of preclusion from working under the Special Procedure in respect of a manufacturer who fails to give timely notice for discontinuation of the procedure.	96V(3)	Asstt. Collector		
4. To exercise over all discretionary powers to apply the provisions of Special Procedure to a manufacturer who has failed to avail himself of the procedure or to comply with any conditions laid down in rules.	96X	*Dy. Collector		*Where there is no Dy. Collector, the power is to be exercised by Collector himself.
IV. Electric Battery parts :				
1. To accept first A.S.P. for grant of permission to work under the Special Procedure.	96Y(1)	Superintendent		
2. To accept first A.S.P. for a period less than the prescribed period.	96Y(2)	Superintendent		
3. To determine the period for which a manufacturer may be precluded from working under the Special Procedure for failure to avail of such procedure during the period for which permission has been granted to him.	96Y(3)	Asstt. Collector		
4. (a) To accept renewal application in form A.S.P.	96Y(4)	Superintendent		
(b) To condone and/or to determine the period of preclusion from working under the Special Procedure in respect of a manufacturer who fails to make an application for renewal.	96Y(4)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 15 days. For condoning delays exceeding 15 days.	
5. To condone failure to make application for removal of excisable goods in form A.R. 9 or to make monthly deposits.	96Z(2)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 5 days. For condoning delays exceeding 5 days.	
6. To exercise overall discretionary powers to apply the provisions of Special Procedure to a manufacturer who has failed to avail himself of the procedure or to comply with any conditions laid down in rules.	96ZZZZ	*Dy. Collector		*Where there is no Dy. Collector, the power is to be exercised by Collector himself.

1	2	3	4	5	6
V.	Plywood :				
1.	To accept first A.S.P. for grant of permission to work under the Special Procedure.	96ZA(1)	Superintendent		
2.	To accept first A.S.P. for a period less than the prescribed period.	96ZA(2)	Superintendent		
3.	To determine the priod for which a manufacturer may be precluded from working under the Special Procedure for failure to avail of such procedure during the period for which permission has been granted to him.	96ZA(3)	Asstt. Collector		
4.	(a) To accept renewal application in form A.S.P.	96ZA(4)	Superintendent		
	(b) Condone and/or to determine the period of preclusion from working under the Special Procedure in respect of a manufacturer who fails to make an application for renewal.	96ZA(4)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 15 days. For condoning delays exceeding 15 days.	
5.	To condone failure to makes application for removal of excisable goods in form A.R. 10 or to make monthly deposits.	96ZD(2)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 5 days. For condoning delays exceeding 5 days.	
6.	To exercise overall discretionary powers to apply the provisions of Special Procedure to a manufacturer who has failed to avail himself of the procedure, or to comply with any conditions laid down in rules.	96ZG	*Dy. Collector		*Where there is no Dy. Collector, the power is to be exercised by Collector himself.
VI.	Embroidery in piece, in strips or in motifs. :				
1.	To accept first A.S.P. for grant of permission to work under the Special Procedure.	96ZH(1)	Superintendent		
2.	To accept first A.S.P. for a period less than the prescribed period.	96ZH(2)	Asstt. Collector		
3.	(a) To accept renewal application in form A.S.P.	96ZH(4)	Superintendent		
	(b) To condone and/or to determine the period of preclusion from working under the Special Procedure in respect of a manufacturer who fails to make an application for renewal.	96ZH(4)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 10 days. For condoning delays exceeding 10 days.	
4.	To condone liability to pay duty at the normal rates on failure to pay compounded levy in time or in the manner prescribed.	96ZI(4)	Asstt. Collector		
5.	To exercise overall discretionary powers to apply the provision of Special Procedure to a manufacturer who has failed to avail himself of the procedure, or to comply with any conditions laid down in rules.	96ZM	*Dy. Collector		*Where there is no Dy. Collector, the power is to be exercised by Collector himself.
VII.	Cotton fabrics processed without the aid of power or steam :				
1.	To accept first A.S.P. for grant of permission to work under the Special Procedure.	96ZO(1)	Superintendent		
2.	To accept first A.S.P. for a period less than the prescribed period.	96ZO(2)	Superintendent		
3.	To determine the period for which a manufacturer may be precluded from working under the Special Procedure for failure to give proper notice for not availing of such procedure during the period for which permission has been granted to him.	96ZO(n)	Asstt. Collector		
4.	(a) To accept renewal application in form A.S.P.	96ZA(4)	Superintendent		

1	2	3	4	5	6
4.	(b) To condone and/or to determine the period of preclusion from working under the Special procedure in respect of a manufacturer who failed to make an application for renewal.	96ZO(4)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 15 days. For condoning delays not exceeding 15 days.	
5.	To condone failure to make application for removal of excisable goods in form A.R. 1 or to make monthly deposits.	96ZQ(2)	Superintendent Asstt. Collector	For condoning delays not exceeding 5 days. For condoning delays exceeding 5 days.	
6.	To exercise overall discretionary powers to apply the provisions of Special Procedure to a manufacturer who has failed to avail himself or the procedure, or to comply with any conditions laid down in rules.	96UU	*Dy. Collector		*Where there is no Dy. Collector, the power is to be exercised by Collector himself.

[Notification No. 2/76 (C No. IV/8/1 CE/73)]

M. L. BADHWAR, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय

चंडीगढ़, 4 सितम्बर, 1976

केन्द्रीय उत्पाद

का०आ० 4301.—मैं के० के० द्विवेदी, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चंडीगढ़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा उप समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क फरीदाबाद को उनके अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत न्याय निर्णय और अपील से संबंधित शक्तियों को छोड़ कर समाहर्ता की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता हूं।

[अधिसूचना सं० 2/के०उ०शु०/76/पत्र सं० 4(16)-72-तक/76]

के० के० द्विवेदी, समाहर्ता

Central Excise Collectorate

Chandigarh, the 4th September, 1976

CENTRAL EXCISES

S.O. 4301.—In exercise of the powers, conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, K. K. Dwivedi, Collector of Central Excise, Chandigarh hereby authorise, the Deputy Collector of Central Excise, Faridabad to exercise, within his jurisdiction, all the powers of the "Collector" under the Central Excise Rules, 1944 except those relating to Adjudication and Appeals.

[Notification No. 2/CE/76/C. No. IV(16)-72-Tech/76]

K. K. DWIVEDI, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4302.—केन्द्रीय सरकार, विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (1961 का 45) की धारा 2 के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि व्यक्तिकारी उपबन्ध बनाए जा चुके हैं, ब्रिटेन को ऐसे राज्य क्षेत्रों के रूप में घोषित करती है, जिस पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची में वर्णित विदेशी माध्यस्थम पंचाट की मान्यता तथा प्रवर्तन संबंधी कन्वेंशन लागू होता है।

[फा० सं० 12(10)/75-ई पी ओ एण्ड]

ए० के० सेन गुप्ता, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 25th October, 1976

S.O. 4302.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act, 1961 (45 of 1961), the Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made, hereby declares the United Kingdom to be territories to which the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, set forth in the Schedule to the said Act, applies.

[F. No. 12(10)/75-E. POI.]

A. K. SENGUPTA, Economic Adviser

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1976

शुद्धि पत्र

का० आ० 4303.—आदेश सं० लैम्प/4(2)75-76/आर०एम-2/1555 दिनांक 4-8-1976 के आंशिक आशोधन में यह उल्लेख किया जाता है कि उसकी पहली पंक्ति में आए हुए शब्द "सर्वश्री अपर प्रा० लि० नई, दिल्ली" को इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :—

"सर्वश्री अपर प्रा० लि०, बम्बई, उसमे पहले सर्वश्री पावर केबल्स प्रा० लि०, बम्बई"।

बाकी विवरण ज्यों के त्यों रहेंगे।

[मि० सं० लैम्प/4(2)/75-76/आर०एम-2/1808]

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

New Delhi, the 27th October, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 4303.—In partial modification of order No. Lamp/4(2)/75-76/RM. II/1555 dated 4-8-1976, it is stated that the words 'M/s. Apar Pvt. Ltd., New Delhi' appearing in the first line therein may be treated as amended to read as under :—

"M/s. Apar Pvt. Ltd., Bombay formerly M/s. Power Cables Pvt. Ltd., Bombay".

The other particulars will remain un-changed.

[No. Lamp/4(2)/75-76/RM. II/1808]

का० आ० 4304.—आदेश सं० लैम्प/4(2)/75-76/आर०एम 2/1556 दिनांक 4-8-1976 के आंशिक आशोधन में यह उल्लेख किया जाता है कि उसकी

पहली पंक्ति में आए हुए शब्द "सर्वश्री अपर प्रा० लि० नई दिल्ली" को इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :—

"सर्वश्री अपर प्रा० लि०, बम्बई उससे पहले सर्वश्री पावर केबल्स प्रा० लि०, बम्बई"

बाकी विवरण ज्यों के त्यों रहेंगे।

[मि० सं० लैम्प/4(2)/75-76/आर०एम० 2/1809]

CORRIGENDUM

S.O. 4304.—In partial modification of order's No. Lamp/4(2)/75-76/RM. II/1556 dated 4-8-1976, it is stated that the words 'M/s. Apar Pvt. Ltd., New Delhi' appearing in the first line therein may be treated as amended to read as under :—

"M/s. Apar Pvt. Ltd., Bombay formerly M/s. Power Cables Pvt. Ltd., Bombay."

The other particulars will remain unchange.

[No. Lamp/4(2)/75-76/RM. II/1809]

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1976

आदेश

का० आ० 4305.—सर्वश्री अपोलो टायर्स लि०, नई दिल्ली को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत कच्चे माल तथा संघटकों का आयात करने के लिए 55,00,000 रुपए के लिए आयात लाइसेंस सं० पी०/डी/1416865/आर/आईएन/58/एच०/41-42/रबर, दिनांक 10-3-76 प्रदान किया गया था।

2. पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंस धारी ने आगे यह भी बताया है कि लाइसेंस उपयोग में नहीं लाया गया है। लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/1416865, दिनांक 10-3-76 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है तथा निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की एक अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिये। मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[मि० सं० रबर/44(1)/75/76 आर० एम० 2/1819]
राजिन्दर सिंह, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 28th October, 1976

ORDER

S.O. 4305.—M/s. Apollo Tyres Ltd., New Delhi were granted Import Licence No. P/D/1416865/R/IN/58/H/41-42/Rubber dated 10-3-1976 under IDA for Rs. 55,00,000/- only for import of Raw materials and Components.

2. The firm have requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost/misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence has not been utilized. The licence has not been registered with any port of India.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The under-signed is satisfied that the original Customs Purposes Copy of Import Licence No. P/D/1416865 dated 10-3-1976 has been lost and directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy is hereby cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes Copy of the licence is being issued separately.

[No. Rubber/44(1)/75-76/RM. II/1819]
RAJINDER SINGH, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

मद्रास, 7 अगस्त, 1976

आदेश

का० आ० 4306.—सर्वश्री इलेक्ट्रोड्स इंडिया, जी-6 इन्डस्ट्रियल इस्टेट, मदुरई-7 को मैंगानिस्ट निकल तार आदि का आयात करने के लिये सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत 18,300 रुपये के लिये लाइसेंस संख्या पी/एस/1833891/सी/एक्स एक्स/57/एम/39-40 दिनांक 16-12-1975 और यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत 18,480 रुपये के लाइसेंस संख्या पी/एस/1833892/आर/एम एल/57/एम/39-40 दिनांक 16-12-1975 प्रदान किये गये थे।

फर्म ने अब उपर्युक्त लाइसेंसों की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस अस्थानस्थ हो गये हैं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूं कि संबंधित उपर्युक्त लाइसेंसों की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां अस्थानस्थ हो गई हैं और उसकी अनुलिपि प्रतियां फर्म को जारी की जायें।

उपर्युक्त लाइसेंसों की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती हैं।

[संख्या इ जी एच एच/445/ए एम-75/एस एस आई]
आर० कुमारवेलु, उप-मुख्य नियंत्रक, कृते मुख्य नियंत्रक,

Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports

Madras, the 7th August, 1976

ORDER

S.O. 4306.—M/s. Electrodes India, G-6, Industrial Estate, Madurai-7 were issued licences No. P/S/1833891/C/XX/57/M/39-40 dated 16-12-1975 for Rs. 18,300/- on GCA and No. P/S/1833892/R/ML/57/M/39-40 dated 16-12-1975 for Rs. 18,480 under U. K. Credit for import of Manganest Nickel wire etc.

The firm have now applied for duplicate of Customs purpose copies of the above said licences on the ground that the original licences have been misplaced. In support of their contention, they have filed an affidavit.

I am satisfied that the original Customs purposes copies of the said licences in question have been misplaced and duplicate copies of the same be issued to the firm.

The original Customs purpose copies of the said licences are hereby cancelled.

[No. EGHH/445/AM-75/SSI-I]
R. KUMARAVELU. Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1976

रद्द करने का आदेश

का० आ० 4307.—सर्वश्री जे० पी० कमल इंजीनियरिंग वर्क्स, ए-69, जी० टी० करनाल रोड, इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली को बिजली की मोटरों के लिये कच्चे माल का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी/एस/1847845 दिनांक 15-6-76 और पी/एस/1847846 दिनांक 15-6-76 प्रत्येक 12085.00 रुपये के लिये प्रदान किये गये थे। उन्होंने सूचना दी है कि उनकी दोनों प्रतियां अर्थात् सीमाशुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिल्कुल उपयोग किये बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

2. उपर्युक्त बयान के समर्थन में फर्म ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैंडबुक 1976-77 के पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंसों की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

3 यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के खंड 9 (सीसी) के अन्तर्गत मेरे लिये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर, मैं उपर्युक्त लाइसेंसों की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों को रद्दद करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक के मामले पर अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं प्रक्रिया विधि हैंडबुक, 1976-77 के पैरा 320 के अनुसार अनुलिपि लाइसेंसों (दोनों प्रतियां) जारी करने के लिये विचार किया जायेगा।

[संख्या एस/जे-2 (एन)/ए एम-76/ए यू यू टी/सी एल ए/2645]

के० आर० धीर, उप-मुख्य नियंत्रक कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports

(Central Licensing Area)

New Delhi, the 1st September, 1976

CANCELLATION ORDER

S.O. 4307.—M/s. J. P. Kamal Engg. Works, A-69, G. T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi were granted import licences Nos. P/S/1847845 dated 15-6-1976 and P/S/1847846 dated 15-6-1976 for Rs. 12085/- each for import of raw materials for Electric Motors. They have reported that both copies i.e. Customs purposes and Exchange Control copies of the same have been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. The firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under Para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1976-77. I am satisfied that the original Custom purposes and Exchange Control purposes of the above licences have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Import Trade Control Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, I order the cancelation of the said original custom purposes and exchange control purposes of the said licences.

4. The applicant's case will now be considered for the issue of duplicate licences (both copies) in accordance with the Para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1976-77.

[No. S/J-2(n)/AM-76/AU-UT/CLA/2645]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller
for Joint Chief Controller

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1976—10—27

का० आ० 4308.— समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे रद्द हो गये हैं और अब वापस माने जायें।

अनुसूची

1	2	3	4
क्रम संख्या	रद्द किये गये भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	भारत के राजपत्र अधिसूचना की एस० ओ० संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी।	विवरण
1.	IS : 1142-1957 ऐलीय पोशकों के कपड़े के लिये चमकदार सूती कैम्ब्रिक की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1958-04-26 में एस० ओ० संख्या 605 दिनांक 1958-04-16 के अन्तर्गत प्रकाशित	यह मानक रक्षा मंत्रालय द्वारा इस वस्तु के स्थान पर लट्ठे प्रयोग में लाने के कारण रद्द कर दिया गया है जिसके लिये भारतीय मानक (IS : 187-1965) पहले से ही निर्धारित है।
2.	IS : 1385-1968 फास्फर कांस छड़ें और सरियें चद्दर और पत्ती और तार की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1968-07-09 में एस० ओ० 2578 दिनांक 1968-07-20 के अन्तर्गत प्रकाशित	यह मानक IS : 7608-1975 फास्फर कांस के तार (सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिये); IS : 7811-1975 फास्फर कांस की छड़ें और सरियों की विशिष्टि तथा IS : 7814-1975 फास्फर कांस की चद्दर, पत्ती और पत्नी की विशिष्टि के प्रकाशन हो जाने के कारण रद्द कर दिया गया है।

[सं० सी एम डी/13 : 7]

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1976-10-27

S.O. 4308.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 1142—1957 Specification for cotton cambric, scoured, for oil dressed fabric.	S.O. 605 dated 1958-04-16 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1958-04-26.	Cancelled as the Ministry of Defence have since replaced this item by long cloth for which an Indian Standard (IS : 187—1965) already exists.
2.	IS : 1385—1968 Specification for phosphor bronze rods and bars, sheet and strip and wire (first revision).	S.O. 2578 dated 1968-07-20 published in the Gazette of India, Part—II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1968-07-09	Cancelled in view of publication of IS : 7608—1975 Specification for phosphor bronze wire (for general engineering purposes); IS : 7811—1975 Specification for phosphor bronze rods and bars and IS : 7814—1975 Specification for phosphor bronze sheet, strip and foil.

[No. CMD/13 : 7]

का० आ० 4309.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिह्न निर्धारित किया है जिसकी डिजाइन, शाब्दिक विवरण और भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1967-03-15 से लागू होगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS:2906 ISI	जलकल कार्यों के लिये स्लूस वाल्व (350 से 1200 मिमी साइज)	IS : 2906-1964 जलकल कार्यों के लिये स्लूस वाल्वों (350 से 1200 मिमी साइज) की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।

[सं० सी एम डी/13 : 9]

S.O. 4309.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notified that the Standard Marks design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1967-03-15 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS:2906 ISI	Sluice valves for water works purposes (350 to 1200 mm size).	IS : 2906—1964 Specification for sluice valves for water works purposes (350 to 1200 mm size).	The monogram of the Indian Standards Institution consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 4310.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किये हैं जिनकी डिजाइनें, शाब्दिक विवरण और भारतीय मानकों के शीर्षकों सहित नीचे अनुसूची में दी गई हैं।

भारतीय मानक संस्था प्रमाणन (चिह्न) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित ये मानक चिह्न उनके आगे दी गई तिथियों से लागू होंगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद-संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		भूरे लोहे की ढली चीजें	IS : 210–1970 भूरे लोहे की ढली चीजों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-04-01
2.		लकड़ी के पेंच तैयार करने में प्रयुक्त कार्बन इस्पात के तार	IS : 1812–1973 लकड़ी के पेंच तैयार करने में प्रयुक्त कार्बन इस्पात के तार की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-10-16
3.		बीड़ियां	IS : 1925–1974 बीड़ियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-10-16
4.		मशीनी पेंच तैयार करने के लिये मृदु इस्पात के तार (शीत सिरे बनाने की विधि द्वारा)	IS : 2255–1969 मशीनी पेंच तैयार करने के लिये मृदु इस्पात के तार की विशिष्टि (शीत सिरे बनाने की विधि द्वारा) (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-01-16
5.		पोशिश स्प्रिंगों के लिये सख्त खिंचे इस्पात के तार	IS : 2589–1964 पोशिश स्प्रिंगों के लिये सख्त खिंचे इस्पात के तार की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-01-16
6.		पानी की सप्लाई के लिये फेरूल	IS : 2692–1964 पानी की सप्लाई के लिये फेरूल की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-10-01
7.		जल, गैस और मल निकास के लिये बिजली द्वारा वेल्डकृत इस्पात के पाइप (200 से 400 मिमी तक सांकेतिक व्यास वाले)	IS : 3589–1966 जल, गैस और मल निकास के लिये बिजली द्वारा वेल्डकृत इस्पात के पाइपों की विशिष्टि (200 से 2000 मिमी तक सांकेतिक व्यास वाले)	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-01-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	IS:4723	अण्डे का पाउडर	IS : 4723-1968 अण्डे के पाउडर की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-12-16
9.	IS:5117	द्रवित पेट्रोलियम गैसों वाले उबालने के व्यापारिक बर्नर	IS : 5117-1969 द्रवित पेट्रोलियम में गैसों वाले उबालने के व्यापारिक बर्नरों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-11-01
10.	IS:6747	च्युइंग-गम और बबूल गम	IS : 6747-1972 च्युइंग-गम और बबूल गम की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-02-01
11.	IS:7193	कांच रेशे के आधार वाली कोलतार रोक पट्टी और बिटयूमेनी नमदें	IS : 7193-1974 कांच के रेशे आधार वाली कोलतार रोकपरटी और बिटयूमेनी नमदों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।	1975-12 01

[सं० सी एम डी/13:9]

ए० बी० राव, उपमहानिदेशक

S.O. 4310—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS:210	Grey iron castings	IS : 210—1970 Specification for grey iron castings (second revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2) ; the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-04-01
2.	IS:1812	Carbon steel wire for manufacture of wood screws	IS : 1812-1973 Specification for carbon steel wire for manufacture of wood screws (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-01-16
3.	IS:1925	BIDIS	IS : 1925—1974 Specification for BIDIS (second revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram	1975-10-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.		Mild steel wire rod for the manufacture of machine screws (by cold heading process)	IS : 2255-1969 Specification for mild steel wire rod for the manufacture of machine screws (by cold heading process) (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-01-16
5.		Hard-drawn steel wire for upholstery springs	IS : 2589-1964 Specification for hard-drawn steel wire for upholstery springs	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact tlyle and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indi cated in the design.	1975-01-16
6.		Ferrules for water services	IS : 2692-1964 Specification for ferrules for water services	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-10-01
7.		Electrically welded steel pipes for water, gas and sewage (200 to 400mm nominal diameter)	IS : 3589-1966 Specification for electrically welded steel pipes for water, gas and sewage (200 to 2000 mm nominal diameter)	The monogram of the Indian Standards Institutions, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-01-01
8.		Egg powder	IS : 4723-1968 Specification for egg powder	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-12-16
9.		Commercial boiling burners for use with LPG	IS : 5117—1959 Specification for commercial boiling burners for use with LPG	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-11-01
10.		Chewing gum and bubble gum	IS : 6747—1972 Specification for chewing gum and bubble gum	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-02-01
11.		Glass fibre base coal tar pitch and bitumen felts	IS : 7193—1974 Specification for glass fibre base coal tar pitch and bitumen felts	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-12-01

[No. CMD/13 : 9]

A. B. RAO, Dy. Director General

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4311.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की रैंक के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, और यह भी निदेश देती है कि उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
नगर इंजीनियर कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लिमिटेड, 25-महात्मा गांधी रोड, बंगलौर (कर्नाटक राज्य)	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड के या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये या अधिग्रहीत स्थान

[सं० 2(22) 76-के डी एम]
एस० डी० प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 29th October, 1976

S.O. 4311:—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be Estate Officer, for the purposes of the said Act and further directs that the said Officer shall exercise of the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

Table

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Town Engineer, Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., 25-Mahatama Gandhi Road, Bangalore (Karnataka State).	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Kudremukh Iron Ore Company Limited.

[No. 2(22)/76-KDM]
S. D. PRASAD, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4312.—यतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जो कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं;

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा तथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है;

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37), यथा अद्यतन संशोधित, की धारा 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं अधिकारी/कर्मचारी का का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन किस पद पर स्थायी है?	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन जिस पद पर थे	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1. श्री एस० पी० सक्सेना	सहायक निदेशक	सहायक निदेशक	1-3-69
2. श्री पी० डी० खेर	गोदाम लिपिक	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-69
3. श्री एम० धनपाल	चौकीदार	चौकीदार	1-3-69
4. श्री एन० चिन्नापा	चौकीदार	चौकीदार	1-3-69
5. मोहम्मद नवाब	गोदाम लिपिक	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-69
6. श्री येलाहिया लक्ष्मइयाह	स्टेचर	स्टचर	1-3-69

[फा० सं० 52/8/73-एफ०सी०-3 (खण्ड 7)]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

Order

New Delhi, 21st October, 1976

S.O. 4312:—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directors of Food, the Procurement Directorates and the Pay and Accounts Offices of the Department of Food which under section 13 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay and Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government, dated the 16th April, 1971, intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (I) of section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date, the Central Government hereby transfers the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No.	Name of the officer/ employee	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the F.C.I.
1	2	3	4	5
1.	Sh. S.P. Saksena	Asst. Dir.	Asstt. Director	1-3-69
2.	Sh. P.D. Kher	Godown Clerk	Sr. Godown Keeper	1-3-69
3.	Sh. M. Dhanapal	Watchman	Watchman	1-3-69
4.	Sh. N. Chinnappa	Watchman	Watchman	1-3-69
5.	Mohd. Nawab	Godown Clerk	Junior Godown Keeper	1-3-69
6.	Sh. Yellaiah/ Lakshmaiah	Stitcher	Stitcher	1-3-69

[No. 52/8/73-FC. III (Vol. VII)]

शुद्धि-पत्र

का० आ० 4313.—इस विभाग के 11 अक्तूबर, 1972 के आदेश संख्या 52/21/68-आर० ई०-1 में निम्नलिखित शुद्धियां कर दी जाएं :—

आदेश में क्रम संख्या	विवरण में की जाने वाली शुद्धियां
1	2
121	कालम 2 में "श्री एस० एम० रेडकर" के स्थान पर "श्रीमती एस० एम० रेडकर" पढ़ें ।
652	कालम 3 में 'वही' के स्थान पर "गोदी निरीक्षक" पढ़ें ।
653	कालम 3 में 'वही' के स्थान पर "तोल लिपिक" पढ़ें ।
1402	कालम 4 में 'वही' के स्थान पर "गोदाम अधीक्षक" पढ़ें ।
1403	कालम 4 में 'वही' के स्थान पर "वरिष्ठ गोदाम रक्षक पढ़ें ।
3261	कालम 2 में 'श्री सूर्यभान' के स्थान पर "श्री सूर्यभान मनगाया" पढ़ें ।
135	कालम 2 में 'श्री टी० एन० केवलरमानी' के स्थान पर "कुमारी टी० एन० केवलरमानी" पढ़ें ।
2509	(i) कालम 2 में 'श्री डी० डी० नारे' के स्थान पर "श्री बी० डी० नारे" पढ़ें ।
	(ii) कालम 4 में 'वही' के स्थान पर "कनिष्ठ गोदाम रक्षक" पढ़ें ।
2510	कालम 4 में 'वही' के स्थान पर "गोदाम लिपिक" पढ़ें ।
2224	कालम 2 में 'श्री एन० सी० पापसारे' के स्थान पर "श्री सी० एन० जापसारे" पढ़ें ।
707	कालम 4 में 'वही' के स्थान पर "तकनीकी अधिकारी" पढ़ें ।
708	कालम 4 में 'वही' के स्थान पर "तकनीकी सहायक" पढ़ें ।
41	कालम 2 में 'श्री जी० ए० टोपका' के स्थान पर "श्री जी० ए० टोपकर" पढ़ें ।

[संख्या 52/22/74-एफ० सी० 3(वाल्यूम-5)]

बख्शी राम, उप सचिव

CORRIGENDUM

S.O. 4313.—In this Department Order No. 52/21/68-REI dated 11-10-1972 the following corrections shall be carried out :—

Sl. No. in the order		Correction to be carried out in the Statement
121		For the words "Shri S.M. Redkar" in col. 2, read "Mrs. S.M. Redkar"
652		For the words "Do" in col. 3, read "Dock Inspector".
653		For the words "Do" in col. 3, read "Weighment Clerk".
1402		For the words "Do" in col. 4, read "Godown Supdt."
1403		For the words "Do" in col. read "Senior Godown Keeper."
3261		For the words "Shri Surya Bhan" in col.2, read "Shri Suryabhan Mangaya."
135		For the words "Shri T.N. Kewalramani" in col. 2, read "Miss T.N. Kewalramani."
2509	(i)	For the words "Shri D.D. Nare" in col. 2, read "Shri B.D. Nare".
	(ii)	For the words "Do" in col. 4, read "Junior Godown Keeper".
2510		For the words "Do" in col. 4, read "Godown Clerk".
2224		For the words "Shri N.C. Papsare" in col. 2, read "Shri C.N. Japsare".
707		For the words "Do" in col. 4, read "Tech. Officer".
708		For the words "Do" in col. 4, read "Tech. Assistant".
41		For the words "Shri G.A Topka" in col. 2, read "Shri G.A. Topkar".

[No. 52/22/74-FCIII(Vol. V)]

BAKHSHI RAM, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4314.—कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1545, तारीख 1 मई, 1976 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 1308.00 एकड़ (लगभग) या 529.30 हैक्टेयर (लगभग) भूमि का कोयले के लिए पर्यवेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि पर कोयला उपलब्ध है

अतः, अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 1308.00 एकड़ (लगभग) या 529.30 हैक्टेयर (लगभग) भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक, 1 कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में, या सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०, (रेवेन्यू सेक्शन), दरभंगा हाऊस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. कोयला नियंत्रक, 1 कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता, उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ।

अनुसूची

ब्लाक 1 और 4 विस्तारण

उप-ब्लाक "क" रेखांक सं० रेव०/31/76

रामगढ़ कोयला क्षेत्र ता० 16-6-76 (जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	कोयहारा	रामगढ़	150	हजारी-बाग		आंशिक
2.	लेहरीटोंगरी	यथोक्त	151	यथोक्त		यथोक्त
3.	जनियमारा	यथोक्त	152	यथोक्त		यथोक्त
4.	गौराबेरा	यथोक्त	153	यथोक्त		यथोक्त
5.	भुचुंगडीह	यथोक्त	154	यथोक्त		यथोक्त
6.	सेवाई	यथोक्त	155	यथोक्त		यथोक्त

कुल क्षेत्र 600.00 एकड़ (लगभग)
अथवा 242.80 हेक्टेयर (लगभग)

गांव कोयहारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

1(पी), 8(पी), 14(पी), 15(पी), 16, 17, 18(पी), 91(पी), 92(पी), 284(पी), 285 और 318(पी) ।

गांव लेहरीटोंगरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

2(पी), 4 से 8, 9(पी), 12(पी), 13. 32(पी). 33(पी). और 35(पी)

गांव जनियामारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

1(पी), और 10(पी) ।

गांव गौराबेरा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

1(पी), 1, 3, 4, 5, 6(पी), 7 से 14, 15(पी), 16, से 22 ।

गांव भुचुंगडीह में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

1(पी), 65(पी, 75(पी), 76, 77, 78 और 79(पी) ।

गांव सेवाई में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

236(पी), 237(पी), 238(पी), 239(पी), 251(पी), 252 से 261, 262(पी), 263(पी), 290(पी), 291(पी), 292(पी), 293(पी), और 294 (पी) ।

सीमा वर्णन

क-ख रेखा गांव कोयहारा में प्लाट संख्या 1 और 15 से हो कर जाती है ।

ख-ग रेखा गांव कोयहारा में प्लाट संख्या 14, 8 और 1 से होकर जाती है ।

ग-घ रेखा दामोदर नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो गांव कोयहारा और गोपो की सामान्य सीमा का भाग भी है) जाती है ।

घ-ङ० रेखा गांव कोयहारा में प्लाट सं० 1, 18, 91, 92 से होकर, गांव गौराबेरा में प्लाट संख्या 1 और 6 से होकर, गांव कोयहारा में प्लाट संख्या 92, 284, 92 और 318 से होकर, गांव सेवाई में प्लाट संख्या 237, 236, 238, 239 और 236 से होकर फिर गांव गौराबेरा में प्लाट सं० 15 से होकर, फिर गांव सेवाई में प्लाट सं० 251, 263, 262, 291, 290, 291, 292, 293 और 294 से होकर और गांव भुचुंगडीह में प्लाट सं० 75 और 79 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 1 की अंशतः सामान्य सीमा है, और का० आ० सं० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा, अर्जित की गई है) जाती है ।

ङ-च रेखा भुचुंगडीह में प्लाट सं० 79, 75 और 65 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 1 की अंशतः सामान्य सीमा है, और का० आ० सं० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित की गई है) जाती है ।

च-छ रेखा गांव भुचुंगडीह में प्लाट संख्या 65 और 1 से होकर, गांव जनियामारा में प्लाट सं० 10 और 1 से होकर, गांव गौराबेरा में प्लाट सं० 1 से होकर, और गांव लेरहीटोंगरी में प्लाट सं० 9, 12, 32, 33 और 35 से होकर जाती है ।

छ-ज रेखा गांव लेरहीटोंगरी में प्लाट संख्या, 35, 33 और 2 से होकर जाती है ।

ज-झ रेखा गांव लेहरहीटोंगरी और कोयहारा की आंशिक सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है ।

झ-क रेखा दामोदर नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ साथ (जो गांव कोयहारा और गोपो की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर जा मिलती है ।

उप-ब्लाक "ख"

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	भुचुंगडीह	रामगढ़	154	हजारी-बाग		आंशिक

कुल क्षेत्र 28.00 एकड़ (लगभग)
अथवा 11.33 हैक्टेयर (लगभग)

गांव भुचुंगडीह में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :—

49(पी), 62(पी), 65(पी), 79(पी), और 240(पी)

सीमा वर्णन

ञ-ट — रेखा गांव भुचुंगडीह में प्लाट सं० 79 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है, और का० आ० सं० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित की गई) जाती है ।

ट-ठ-ड-ढ-ण — रेखाएं गांव भुचुंगडीह में प्लाट सं० 79, 62 और 240 से होकर जाती हैं ।

ण-त — रेखा भोरा नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (जो गांव भुचुंगडीह और बांदा की सामान्य सीमा का भाग है) जाती है ।

त-थ-द-ध-ञ — रेखाएं गांव भुचुंगडीह में प्लाट सं० 240, 49, 62, और 65 से होकर जाती हैं और प्रारम्भिक बिन्दु "ञ" पर जा कर मिलती हैं ।

उप-ब्लाक "ग"

सभी अधिकार

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	सेवाई	रामगढ़	155	हजारी-बाग		आंशिक
2.	हुटुगबाग	यथोक्त	156	यथोक्त		यथोक्त
3.	तेवरबाग	यथोक्त	158	यथोक्त		यथोक्त
		कुल क्षेत्र :—		90.00 एकड़ (लगभग)		
		अथवा		36.42 हेक्टेयर (लगभग)		

गांव सेवाई में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :—

998(पी), 999(पी), 1000 से 1024, 1025(पी), 1026, 1027(पी) 1028(पी), 1029(पी), 1034(पी), 1134(पी), 1135, 1136, 1137(पी), 1138(पी)

गांव हुटुगबाग में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :—

1, 2, 3, 4(पी), 5, 6, 7, 9(पी), 9(पी), 11(पी), 12 से 21, 22(पी), 23(पी), 24(पी), 25(पी), 54(पी), 56, 57(पी), 64 से 72, 149 (पी), 151(पी), 153(पी), 154(पी), 158(पी), 161(पी), 162(पी), 163(पी), 164(पी), 165, 166(पी), 167 से 170, 171(पी), 177(पी), 178(पी), 179(पी), 180, 181, 18(पी) 183, 184, 185(पी) 186(पी), 190(पी), 191(पी), 192(पी), 193 से 199 और 200(पी) ।

गांव तेवरबाग में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :—

361(पी) और 362(पी)

सीमा वर्णन

क 1-क 2 — रेखा गांव सेवाई में प्लाट संख्या 1025 से होकर प्लाट सं० 986 की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्या 1034 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है और का० आ० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित की गई है जाती है ।

क 2-क 3 — रेखा गांव सेवाई में प्लाट सं० 1025, 998, 1137 और 1138 से होकर और गांव सेवाई में प्लाट सं० 25, 24, 23, 22, 25, 192 और 191 से होकर (जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित ब्लाक की आंशिक सामान्य सीमा भी है) जाती है ।

क 3-क/4- क/5-क/6- क/7-क/8 — रेखाएं प्लाट संख्या 191, 190, 185, 186 से होकर प्लाट सं० 186, 187, 63 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 55 की पूर्वी सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 57 से होकर प्लाट सं० 54 से होकर, प्लाट सं० 83 की आंशिक उत्तरी सीमा के साथ साथ, प्लाट सं० 82, 81, 73, 160 की उत्तरी सीमा के साथ साथ, फिर प्लाट सं० 164 की आंशिक उत्तरी सीमा के साथ साथ, गांव हुटुगबाग में प्लाट संख्या 164, 163, 162, 161, 158, 154, 153, 151, से होकर, गांव तेवरबाग में प्लाट सं० 362 और 361 से होकर और फिर गांव हुटुगदाग में प्लाट सं० 149 से होकर जाती है ।

क/8-क/9 — रेखा गांव हुटुगदाग में प्लाट सं० 149 से होकर, गांव तेवरबाग में प्लाट संख्या 361 और 362 से होकर, फिर गांव हुटुगबाग में प्लाट सं० 154, 166, 171, 179, 178, 179, 177 और 200 से होकर जाती है ।

क/9-क/1 — रेखा गांव हुटुगबाग में प्लाट सं० 200, 11, 9, 8 और 4 से होकर, गांव सेवाई में प्लाट सं० 1134, 1029, 1028, 1027 और 1034 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है, और का० आ० 3894 तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित की गई थी) जाती है और बिन्दु क।1 पर जा कर मिलती है ।

उप-ब्लाक 'घ'

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	सनरी	रामगढ़	157	हजारीबाग		आंशिक
		कुल क्षेत्र :-		55.00 एकड़ (लगभग)		
		अथवा		22.25 हेक्टेयर (लगभग)		

गांव सनरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या:—

277(पी), 288(पी), 289(पी), 290, 291(पी), 292 (पी), 293(पी), 294(पी), 295(पी), 296 से 311, 312(पी), 313 से 344, 245(पी), 347(पी), 348(पी), 350(पी), 351, 352, 353(पी), 354(पी), 359(पी), 360(पी), 361(पी), 368(पी),

369 से 371, 372(पी), 373, 378(पी), 379(पी), 380(पी), 381 से 403, 404(पी), 405(पी), 410(पी), 411 से 417, 418(पी), 424(पी), 428(पी), 429, 430, 431(पी), 432 से 437, 438(पी), 439 से 444, 445(पी), 461(पी), 462 (पी), 463(पी), 464(पी), 465(पी), 475(पी), 476(पी), 477, 478, 479(पी), 482(पी), 483(पी), 484 से 491, 492 (पी), 494(पी), 495, 496(पी), 510(पी), 511(पी), 512(पी), 513, 514, 515, 516(पी), 517(पी), 518 से 541, 542(पी), 543 (पी), 544(पी), 547(पी), 572(पी), 573, 574, 575 (पी), 681(पी), 682(पी), 684(पी), 688(पी), 689(पी), 690 (पी), 707, 709, 710, 711 ।

सीमा वर्णन:—

क/10-क/11 रेखा गांव सनरी में प्लाट संख्या 345 की सड़क की आंशिक पश्चिमी सीमा से ही होकर जाती है (जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित ब्लाक की आंशिक सामान्य सीमा भी है) ।

क/11-क/12 रेखा गांव सनरी में प्लाट संख्या 345, 277, 294, 295, 293, 292, 291, 288, 289, 312, 575, 572, 542, 543, 544, 547, 511, 512, 510, 516, 517, 492, 494, 496, 482, 483, 479, 475, 476, 465, 464, 463, 462, 461, 445, 681 और 690 से होकर जाती है ।

क/12-क/10 रेखा गांव सनरी में प्लाट संख्या 690, 689, 688, 682, 438, 684, 424, 428, 431, 418, 410, 405, 404, 379, 380, 378 से होकर, प्लाट सं० 374 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 372, 368, 361, 360, 359, 354, 353, 350, 348, 347 और 345 से होकर जाती है (जो भूमि अर्जित अधिनियम के अधीन अर्जित ब्लाक की आंशिक सामान्य सीमा भी है) ।

उप-ब्लाक "ड"

सभी अधिकार (जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है)

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	माएल	रामगढ़	148	हजारीबाग		आंशिक
2.	सेवाई	यथोक्त	155	यथोक्त		आंशिक

कुल क्षेत्र : 535.00 एकड़ (लगभग)
अथवा 216.50 हैक्टेयर (लगभग)

गांव माएल में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या:—

293(पी), 313(पी), 314(पी), 317(पी), 318 से 351, 352(पी), 433(पी), 475(पी), 477(पी), 481(पी), 482 (पी), 484(पी), 485(पी), 486, 487(पी), 488 से 507, 508 (पी), 509 से 537, 538(पी), 540(पी), 543(पी), 544(पी), (पी), 545 (पी), 582(पी), 583, 584(पी), 617(पी), 618(पी), 619, 620(पी), 621(पी), 622 से 635, 636(पी), 637(पी), 638 से 647, 648(पी), 649(पी), 650(पी), 651 से 656, 657 (पी), 658, 721(पी), 623(पी), [illegible] 725(पी), 726 (पी) 727(पी), 728(पी), 734(पी), 736(पी), 737(पी), 738 से 741, 742(पी), 743(पी), 744(पी), 745 से 750, 751 (पी), 752(पी), 753(पी), 754, 755, 756(पी), 757, 758, 759, 760(पी), 823(पी), 824(पी), 825(पी), 826, 827, 828(पी), 840(पी), 841 से 862, 863(पी), 865(पी), 866, 867(पी), 868(पी), 869 870, 871(पी), 872(पी), 3294 (पी), 4215 ।

गांव सेवाई में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या:—

700(पी), 705(पी), 706(पी), 707 से 711, 712 (पी), 713(पी), 723(पी) 724 से 727 728(पी), 729(पी), 730 से 737, 738(पी), 741(पी), 742, 743(पी), 744 से 953, 954(पी), 955(पी), 956 से 971, 972(पी), 973 से 985, 1034(पी), 1188 से 1207, 1208(पी), 1209 से 1246, 1247 (पी), 1305(पी), 1306, 1307, 1308, 1310 से 1328, 1329 (पी), 1330, 1386 ।

सीमा वर्णन :—

क/13-क/14 रेखा गांव माएल में प्लाट संख्या 724, 723, 724, 725, 726, 727, 726, 728, 736, 734, 737, 742, 743, 744, 760, 637, 636, 823, 824, 825, 828, 840, 863, 865, 867, 868, 871, 872, 681, 487, 484, 485, 482, 481, 477, 475, 433, 352, 538, 540, 543, 352, 3294 और गांव सेवाई में प्लाट संख्या 1329 से होकर जाती है ।

क/14-क/15 रेखा गांव सेवाई में प्लाट संख्या 1329 से होकर जाती है ।

क/15-क/16-क/17 क/18-क/19-क/20 रेखाएं गांव सेवाई में प्लाट संख्या 1329 की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्या 1208 से होकर जाती हैं ।

क/20-क/21 रेखा सड़क की आंशिक पश्चिमी सीमा के साथ साथ और गांव सेवाई में प्लाट संख्या 972, 955, 954 और 1034 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है और का० आ० 3894, तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित की गई थी) जाती है ।

क/21-क/22 रेखा सेवाई गांव में प्लाट संख्या 1034, 723, 728, 729, 738 से होकर प्लाट सं० 737 की आंशिक उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्या 741, 743, 712, 713, 705, 706, 700, 1247, 700, 1247, 700, और 1305 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 1 की आंशिक सामान्य सीमा भी है, और का० आ० 3894, तारीख 22-12-62 द्वारा अर्जित की गई थी) जाती है ।

क-22-क/23 रेखा सेवाई और माएल गांवों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ साथ (जो कोयला अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 4 की आंशिक सामान्य सीमा भी है, और का० आ० 2777, तारीख 4-8-64 द्वारा अर्जित की गई थी) जाती है ।

क/23-क/13 रेखा गांव माएल में प्लाट संख्या 293, 313, 314, 317, 544, 545, 544, 582, 584, 508, 584, 618, 617, 620, 621, 648, 649, 650, 657, 756, 753, 752,

731, 726, 721, 724, 723 और 724 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 4 की आंशिक सामान्य सीमा भी है, का० आ० 2777 तारीख 4-8-64 द्वारा अर्जित की गई थी) जाती है।

[सं० 19(ii)/76-सी० एल]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 25th Oct., 1976

S.O. 4314.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1545 dated 1st. May, 1976, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intension to prospect for coal in 1308.00 acres (approx.) or 529.30 hectares (approx.) of the lands in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands;

Now, therefor, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intension to acquire the lands measuring 1308.00 acres (approx.) or 529.30 hectares (approx.) described in the schedule appended hereto.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Central Coalfields Ltd., (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi, (Bihar).

3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act.

SCHEDULE

Block I & IV Extn. Drg. No. Rev/31/76
Sub-Block 'A' Dt. 16-6-76
Ramgarh Coalfield (Showing lands to be acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Koihara	Ramgarh	150	Hazaribagh	Part	
2.	Lerhitongri	—do—	151	—do—	—do—	
3.	Janiamara	—do—	152	—do—	—do—	
4.	Gaurabera	—do—	153	—do—	—do—	
5.	Bhuchungdih	—do—	154	—do—	—do—	
6.	Sewai	—do—	155	—do—	—do—	

Total area: 600.000 acres (approx.)
or 242.80 hectares (approx.)

Plot numbers to be acquired in village Koihara:—
1(p), 8 (p), 14(p), 15 (p). 16, 17, 18(p), 91(p), 92(p), 284 (p), 285 & 318(p).

Plot numbers to be acquired in village Lerhitongri:—
2(p), 4 to 8, 9(p), 12(p), 13, 32(p), 33(p) & 35(p).

Plot numbers to be acquired in village Janiamara:—
1(p), & 10(p),

Plot numbers to be acquired in village Gaurabera:—
1(p), 2, 3, 4, 5, 6(p), 7 to 14, 15(p), 16 to 22.

Plot numbers to be acquired in village Bhuchungdih:—
1(p), 65(p), 75(p), 76, 77, 78 & 79(p).

Plot numbers to be acquired in village Sewai:—
236(p), 237(p), 238(p), 239(p). 251(p), 252 to 261, 262(p), 263(p), 290(p), 291(p), 292(p), 293(p), & 294(p).

Boundary Description:—

A—B	Line passes through plot numbers 1 & 15 in village Koihara.
B—C	Line passes through plot numbers 14, 8, and 1 in village Koihara.
C—D	Line passes along the part central line of Damodar Nadi (which is also part common boundary of villages Koihara & Gopo).
D—E	Line passes through plot numbers 1, 18, 91, 92 in village Koihara, through plot numbers 1 and 6 in village Gaurabera again through plot numbers 92, 284, 92 and 318 in village Kaihara, through plot numbers 237, 236, 238, 239 and 236, in village Sewai again through plot number 15 in village Gaurabera again through plot numbers 251, 263, 262, 291, 290, 291, 292, 293 and 294 in village Sewai and through plot numbers 75 and 79 in village Bhuchungdih [which is also the part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9(1) of the Coal Act] vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62).
E—F	Line passes through plot numbers 79, 75 and 65 in village Bhuchungdih (which is also part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9 (1) of the Coal Act vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62).
F—G	Line passes through plot numbers 65 and 1 in village Bhuchungdih, through plot numbers 10 and 1 in village Janiamara, through plot number 1 in village Gaurabera through plot numbers 9, 12, 32, 33 and 35 in village Lerhitongri.
G—H	Line passes through plot numbers 35, 33 and 2 in village Lerhitongri.
H—I	Line passes along the part common boundary villages Lerhitongri and Koihara.
I—A	Line passes along the part central line of Damodar Nadi (which is also the part common boundary of village Koihara and Gopo) and meets at starting point 'A'.

Sub-Block 'B'
(Showing lands to be acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Bhuchungdih	Ramgarh	154	Hazaribagh	Part	

Total area: 28.00 acres (approx.)
or 11.33 hectares (approx.)

Plot numbers to be acquired in village Bhuchungdih:—
49(p), 62(p), 65(p), 79(p), and 240(p).

Boundary Description:—

J—K Line passes through plot number 79 in village Bhuchungdih (which is also the part common boundary of Ramgarh Block-I acquired u/s 9 (1) of the Coal Act, vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62.

K—L—M—N—O Lines pass through plot numbers 79, 62 and 240 in village Bhuchungdih.

O—P Line passes along the part central line of Bhera Nadi (which is also the part common boundary of villages Bhuchuhgdih and Banda).

P—Q—R—S—J Lines pass through plot numbers 240, 49, 62 and 65 in village Bhuchungdih and meet at starting point 'J'.

Sub-Blocks—'C'

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sewai	Ramgarh	155	Hazaribagh	Part	
2.	Hutugdag	—do—	156	—do—	—do—	
3.	Tewardag	—do—	158	—do—	—do—	
		Total area or	90.00 acres (approx.) 36.42 hactares (approx.)			

Plot numbers to be acquired in village Sewai:—

998(p), 999(p), 1000 to 1024, 1025(p), 1026, 1027(p), 1028 (p), 1029(p), 1034(p), 1134(p), 1135(p), 1136, 1137(p), 1138 (p).

Plot numbers to be acquired in village Hutugdag:—

1, 2, 3, 4(p), 5, 6, 7, 8(p), 9(p), 11(p), 12 to 21, 22(P), 23(p) 24(p), 25(p), 54(p), 56, 57(p), 64 to 72, 149(p), 151(p), 153 (p), 154(p), 158(p), 161(p), 162(p), 163(p), 164(p), 165, 166(p), 167 to 170, 171(p), 177(p), 178(p), 179(p), 180, 181, 182, 183, 184, 185(p), 186(p), 190(p), 191(p), 192(p), 193 to 199 and 200 (p).

Plot numbers to be acquired in village Tewardag:—

361 (p) and 362(p).

Boundary Description:—

A/1—A/2 Line passes through plot numbers 1034 along part eastern boundary of plot no. 986 through plot no. 1025 in village Sewai (which is also the part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9 (1) of the Coal Act, vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62).

A/2—A/3 Line passes through plot numbers 1025, 998, 998, 1137 and 1138 in village Sewai through plot numbers 25, 24, 23, 22, 25, 192 and 191 in village Sewai (which is also the part common boundary of the block acquired under L.A. Act).

A/3—A/4—A/5—A/6—A/7—A/8 Lines pass through plot numbers 191, 190, 185, 186, along southern boundary of plot numbers 186, 187, 63 through plot number 57 along eastern boundary of plot number 55 through plot number 54, along part northern boundary of plot number 83, along northern boundary of plot numbers 82, 81, 73, 160, then along part northern boundary of plot number 164, through plot numbers 164, through plot numbers 164, 163, 162, 161, 158, 154, 153, 151 in village Hutugdag, through plot numbers 362 and 361 in village Tewardag, again through plot number 149 in village Hutugdag.

A/8—A/9 Line passes through plot numbers 149 in village Hutugdag through plot number 361 and 362 in village Tewardag, again through plot numbers 154, 166, 171, 179, 178, 179, 177 and 200 in village Hutugdag.

A/9—A/1 Line passes through plot numbers 200, 11, 9, 8 and 4 in village Hutugdag, through plot numbers 1134, 1029, 1028, 1027 and 1034 in village Sewai (which is also the part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9(1) of the Coal Act, vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62) and meets at starting point A/1.

Sub-Block—'D'

All Rights (Showing lands to be acquired)

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sanri	Ramgarh	157	Hazaribagh	Part	
		Total area: or	55.00 acres (approx.) 22.25 hectares (approx.)			

Plot numbers to be acquired in village Sanri:—

277(p), 288(p), 289(p), 290, 291(p), 292(p), 293(p), 294(p), 295(p), 296 to 311, 312(p), 313 to 344, 245(p), 347(p), 348(p), 350(p), 351, 352, 353(p), 354(p), 359(p), 360(p), 361 (p), 368(p), 369 to 371, 372(p), 373, 378(p), 379(p), 380(p), 381 to 403, 404(p), 405(p), 410(p), 411 to 417, 418(p), 424(p), 428(p), 429, 430, 431(p), 432 to 437, 438 (p), 439 to 444, 445(p), 461(p), 462(p), 463(p), 464(p), 465(p), 475(p), 476(p), 477, 478, 479(p), 482(p), 483(p), 484 to 491, 492(p), 494(p), 495, 496(p), 510(p), 511(p), 512(p), 513, 514, 515, 516(p), 517(p), 518 to 541, 542(p), 543(p), 544(p), 547(p), 572(p), 573, 574, 575(p), 681(p), 682(p), 684(p), 688(p), 689(p), 690(p), 707, 709, 710, 711.

Boundary Description:—

A/10—A/11 Line passes only the part western boundary of road of plot number 345 in village Sanri (which is also the part common boundary of block acquired under L.A. Act.)

A/11—A/12 Line passes through plot numbers 345, 277, 294, 295, 293, 292, 291, 288 289, 312, 575, 572, 542, 543, 544, 547, 511, 512, 510, 516, 517, 492, 494, 496, 482, 483, 479, 475, 476, 465, 464, 463, 462, 461, 445, 681, 690 in village Sanri.

A/12—A/10 Line passes through plot numbers 690, 689, 688, 682, 438, 684, 424, 428, 431, 418, 410, 405, 404, 379, 380, 378 along southern boundary of plot no. 374 through plot nos. 372, 368, 361, 360, 359, 354, 353, 350, 348,347 and 345 in village Sanri (which is also the part common

boundary of Block acquired under L.A. Act) and meets at starting A/10.

Sub-Block 'E'

All Right (Showing lands to be acquired)

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District Area	Remarks
1.	Mael	Ramgarh	148	Hazaribagh	Part
2.	Sewai	—do—	155	—do —	Part.
		Total area:	535.00 acres (approx.)		
		or	216.50 hectares (approx.)		

Plot numbers to be acquired in village Mael:—

293(p), 313(p), 314(p), 317(p), 318 to 351, 352(p), 433(p), 475(p), 477(p), 481(p), 482(p), 484(p), 485(p), 486, 487(p), 488 to 507, 508(p), 509 to 537, 558(p), 540, (p), 453(p), 544(p), 545 (p), 582(p), 583 584(p), 617(p), 618(p), 619, 620(p), 621(p), 622 to 635, 636(p), 637(p), 638 to 647, 648(p), 649(p), 650(p), 651 to 656, 657(p), 658, 721(p), 623(p), 724(p), 725(p), 726(p), 727 (p), 728(p), 734(p), 736(p), 737(p), 738 to 741, 742(p), 743(p), 744(p), 745 to 750, 751(p), 752 (p), 753(p), 754, 755, 756(p), 757, 758, 759, 760(p), 823(p), 824(p), 825(p), 826, 827, 828(p), 840(p), 841 to 862, 863(p), 865(p), 866, 867(p), 868(p), 869, 870, 871(p), 872(p), 3294(p), 4215,

Plot number to be acquired in village Sewai:—

700(p), 705(p), 706(p), 707 to 711, 712(p), 713(p), 723(p) 724 to 727, 728(p), 729(p), 730 to 737, 738(p), 741 (p), 742, 743(p) 744 to 953(p), 954 (p), 955 (p), 956 to 971, 972(p), 973 to 985, 1034(p), 1188 to 1207, 1208(p), 1200 to 1246, 1247(p), 1305(p), 1306, 1307, 1308, 1310 to 1328, 1329(p), 1330, 1386.

Boundary Description:—

A/13- A/14	line passes through plot numbers 724, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 736, 734, 737, 742, 743, 744, 760, 637, 636, 823, 824, 825, 828, 840, 863, 865, 867, 868, 871, 872, 681, 487, 484, 485, 482, 481, 477, 475, 433, 352, 538, 540, 543, 352, 3294 in village Mael and through plot number 1329 in village Sewai.
A/14- A/15	line passes through plot number 1329 in village Sewai.
A/15- A/16—A/17 A/18- A/19- A/20	Lines pass through plot number 1329 along part eastern boundary of plot number 1329 through plot number 1208 in village Sewai.
A/20- A/21	line passes along the part western boundary of road and through plot numbers 972, 955, 954 and 1034 in village Sewai (which is also the part common boundary of block acquired under L.A. and part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9(1) of the Coal act vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62).
A/21—A/22	line passes through plot numbers, 1034 723, 728, 729, 738 along part northern boundary of plot no. 737 through plot nos. 741, 743, 712, 715, 705, 806, 700 1247, 700, 1247, 700 and 1305 in village Sewai (which is also the part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9(1) of the Coal Act vide S.O. No. 3894 dt. 22-12-62).
A/22- A/23	line passes along the part common boundary of villages Sewai and Mael (which is also the part common boundary of Ramgarh Block IV acquired u/s 9(1) of the Coal act, vide S.O. No. 2777 dt. 4-8-64).
A/23—A/13	line passes through plot numbers 293, 313, 314, 317, 544, 545, 544, 582, 584, 508, 584, 618, 617, 620, 621, 648, 649, 650, 657, 756, 753, 752, 751, 726, 721, 724, 723, and 724 in village Mael (which is also the part common boundary of Ramgarh Block IV acquired u/s 9(1) of the Coal Act vide S.O. No. 2777 dt. 4.8.64).

[No. 19 (11)/76—CL.]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4315.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमियों में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सी० एम० ई० (प्लैनिंग), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यालय, दिशेरगढ़, जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल में या कलक्टर, बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय, में या कोयला नियन्त्रक के कार्यालय, 1-काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकेगा ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमियों में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शे, चार्ट और अन्य दस्तावेजें, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) नियम, 1957 के नियम 5 द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर सी०एम० ई० (प्लैनिंग) ईस्टर्न कोलफिल्डस् लिमिटेड, दिशेरगढ़ को परिदत्त कर देगा ।

अनुसूची

रानीगंज कोयला-क्षेत्र

का० सं० 33/1858

तारीख 18-2-76

क्रम सं०	मौजा	थाना संख्या	पुलिस थाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	गंगुटिया	28	कुल्टी	बर्दवान		भाग
2.	छोटा डेमुआ	42	,,	,,		पूर्ण
		कुल क्षेत्र :	437.43 एकड़ (लगभग)			
		या	177.05 हेक्टेयर (लगभग)			

सीमा वर्णन :

क—ख	रेखा मौजा गंगुरिया (पूर्व पश्चिम में) से होकर जाती है ।
ख—ग	रेखा मौजा गंगुरिया की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है ।
ग—घ	रेखा मौजा छोटा डेमुआ की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है।
घ—क	रेखा मौजा छोटा डेमुआ की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है ।

ङ—च रेखा मौजा छोटा ढेमुआ की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है ।

च—क रेखा मौजा गंगुटिया की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है ।

[सं० 19(18)/76-सी एल]

चन्द्र धर त्रिपाठी, निदेशक

New Delhi, the 26th October, 1976

S.O. 4315.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the C.M.E. (Planning), Eastern Coalfields Ltd., Dishergarh, Dist. Burdwan, West Bengal, or in the office of the Collector, Burdwan (West Bengal) or in the office of the Coal Controller 1-Council House Street, Calcutta.

Any person interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the C.M.E. (Planning), Eastern Coalfields Limited, Dishergarh, within ninety days from the date of the publication of this notification in the Gazette of India, as required by rule 5 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and development) Rules, 1957.

SCHEDULE

RANIGANJ COALFIELD

Drg. No. 33/1858
Dated 18-2-76

Sl. No.	Mouza	Thana number	Police station (Thana)	District Area	Remarks
1.	Gangutia	28	Kulti	Burdwan	Part
2.	Chhota Dhemua	42	,,	,,	Full

Total Area—437.43 Acres (approximately) or 177.05 Hectares (approximately)

Boundary Description:

A—B Line passing through Mouza Gangutia (due East-West)

B—C Line following the eastern boundary of Mouza Gangutia

C—D Line following the Eastern boundary of Mouza Chhota Dhemua

D—E Line following the Southern Boundary of Mouza Chhota Dhemua

E—F Line following the Western Boundary of Mouza Chhota Dhemua

F—A Line following the Western Boundary of Mouza Gangutia.

[No. 19 (18) 76—CL]

C. D. TRIPATHI, Director.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4316.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने दमोह टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-11-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-5/76-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 28th October, 1976

S.O. 4316.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-11-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Damoh Telephone Exchange, M. P. Circle.

[No. 5-5/76-PHB]

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4317.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने चंदौसी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-12-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-3/76-पी एच बी]

New Delhi, the 29th October, 1976

S.O. 4317.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-12-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Chandausi Telephone Exchange, U.P. Circle.

[No. 5-3/76-PHB.]

का० आ० 4318.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने राणाघाट टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-11-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-14/76-पी एच बी]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक

S.O. 4318.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-11-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Ranaghat Telephone Exchange, West Bengal Circle.

[No. 5-14/76-PHB.]

P. C. GUPTA, Assistant Director General

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जून, 1976

का० आ० 4319.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पुंजार ट्रान्सपोर्ट सर्विस, एराट्टुपेट. कोण्डुर गांव, मीनाचिल तालुक, कोट्टयम

जिला, केरल, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1975 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(206)/75-पी० एफ० 2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd June, 1976

S.O. 4319.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Poonjar Transport Service, Erattupetta, Kondoor Village, Meenachil Taluk, Kottayam District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1975.

[No. S. 35019(06)/75-PF. II]

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4320—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शालीमार फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, 13 ब्रैबोर्न रोड, कलकत्ता, (रजिस्टर्ड आफिस) जिसमें एल-22 हावरा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पो० आ० बाटीकुर्टी, दास नगर, हावरा स्थित इसका कारखाना भी सम्मिलित है । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(13)/76 पी० एफ० 2]

New Delhi, the 27th October, 1976

S.O. 4320.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shalimar Forgings Private Limited, 13, Brabourne Road, Calcutta-41 (Registered Office) and including its Factory at L. 22, Howrah Industrial Estate, Post Office Baltikuri, Dasnagar, Howrah, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1975.

[No. S. 35017/13/76-PF. II]

का०आ० 4321.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1974 मैसर्स वालप्लेक्स उद्योग, नन्दधाम औद्योगिक इस्टेट, ब्लाक सं० ई-7-12, मारोल ग्राम, अन्धेरी (पूर्वी) मुम्बई-59 जिसके अन्तर्गत 207 अरुण चेम्बर्स, तारदेव रोड, मुम्बई-59 स्थित इसकी शाखा भी है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018(57)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 4321.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1974, the establishment known as Messrs Valplex Industries, Nand Dham Industrial Estate, Block No. E-7-1, Marol Village, Andheri (East) Bombay-59, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/57/75-PF. II(ii)]

का०आ० 4322.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1975 से मैसर्स गेमिको, 697/6, रेड मार्ग, अहमदाबाद, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019/138/76-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 4322.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of March, 1975 the establishment known as Messrs Gamico, 697/6, Raid Road, Ahmedabad, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(138)/76-PF. II/(ii)]

का०आ० 4323—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भगत सिल्क मिल्स, रामपुरा, पुराना बालाश्रम, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(366)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 4323.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bhagat Silk Mills, Rampura, Old Balashram, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1976.

[No. S. 35019/360/76-PF. II]

का०आ० 4324.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरसन फैब्रिक्स, फुलपाड़ा, मेन रोड, कतारगाम, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(365)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 4324.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harson Fubrics, Fulpada, Main Road, Katargam, Surat, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1976.

[No. S. 35019/365/76-PF. II]

का०आ० 4325.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दीप्ति टैक्सटाइल्स, ए० के० रोड, गांधी नगर, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(366)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 4325.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dipti Textiles, A. K. Road, Gandhi Nagar, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1976.

[No. S. 35019/366/76-PF. II]

का०आ० 4326.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिलायबुल उड इण्डस्ट्रीज, 4/1293, जलवाड टेकरा, मोती सिनेमा के पीछे, सूरत-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(367)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 4326.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Reliable Wood Industries, 4/1293, Zalawad Tekra, Behind Moti Cinema, Surat-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1976.

[No. S. 35019/367/76-PF. II]

का०आ० 4327.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स छोटेभाई टी० काडीवाला, 33/1, प्लोट सं० 5, जेल के पीछे, खटोदरा, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(374)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 4327.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chhotubhai T. Kadiwala, 33/1, Plot No. 5, Behind Jail, Khatodra, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1976.

[No. S. 35019/374/76-PF. II]

का०आ० 4328.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि खजिया वायु नियंत्रक निगम, लाल दरवाजा, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(376)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 4328.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lakhia Airconditioning Corporation Lal Darwaja, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1973.

[No. S. 35019/376/76-PF. II]

का०आ० 4329.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1973 से मैसर्स लखिया वायु नियंत्रक निगम, लाल दरवाजा, अहमदाबाद नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(376)/76-पी० एफ० 2 ii]

S.O. 4329.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of March, 1973, the establishment known as Messrs Lakhia Air Conditioning Corporation, Lal Darwaja, Ahmedabad, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/376/76-PF. II(ii)]

का०आ० 4330.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साम ट्रेडर्स डिंडिगल रोड, कारूर, त्रीची जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/378/76-पी० एफ० 2]

S.O. 4330.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sam Traders, Dindigul Road, Karur, Trichy District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019/378/76-PF. II]

का०आ० 4331.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स अंजना वीविंग वर्क्स, नानी बेगमवाडी, सलाबतपुरा, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(380)/76-पी० एफ० 2]

S.O. 4331.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anjana Weaving Works, Nani Begamwadi Salabatpura, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1976.

[No. S. 35019/380/76-PF. II]

का० आ० 4332.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स रसिकलाल चिमन लाल, नानी बेगमवाडी सलाबतपुरा, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(381)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 4332.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ratilal Chimanlal, Nani Begamwadi, Salabatpura, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35019/381/76-PF. II]

का० आ० 4333.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स रसिकलाल चिमनलाल, नानी बेगमवाडी—सलाबतपुरा, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(382)/76-पी० एफ-2]

S.O. 4333.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rasiklal Chimanlal, Nami Begamwadi, Salabatpura, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35019/382/76-PF. II]

का० आ० 4334.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स अशोक विविंग वर्क्स नामी बेगामवाडी, सलाबतपुरा, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(384)/76-पी० एफ-2]

S.O. 4334.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ashok Weaving Works, Nani Bagamwadi, Salabatpura, Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35019/384/76-PF. II]

का० आ० 4335.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स रविकान्त चिमनलाल, नानी बेगमवाडी सलाबतपुरा, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(385)/76-पी० एफ-2]

S.O. 4335.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ravikant Chimanlal, Nani Begamwadi, Salabatpura, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35019/385/76-PF. II]

का० आ० 4336.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स हिमाचल प्रदेश वन निगम, रेसिन डिवीजन मंडी (हिमाचल प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(386)/76-पी० एफ-2(i)]

S.O. 4336.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the Establishment known as Messrs. H. P. State Forest Corporation, Resin Division, Mandi (Himachal Pradesh) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35019/386/76-PF. II(i)]

का० आ० 4337.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रबन्ध शक्तियों का प्रदत्त करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जाँच करने के पश्चात् 1 मई, 1976 से मेसर्स हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम, रेसिन डिवीजन, मंडी (हिमाचल प्रदेश) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(386)/76-पी० एफ-2(ii)]

S.O. 4337.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of May, 1976 the establisment known as Messrs H. P. State Forest Corportation, Resin Division, Mandi (Himachal Pradesh) for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35019/386/76-PF. II(ii)]

का० आ० 4338.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि नानजी टोपने भट्ट एण्ड कम्पनी, बाजार रोड, कोचिन-2 कट्टनचेरी गाँव, कोचीन तालुक, एर्नाकुलम जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और

कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(388)/76-पी० एफ-2]

S.O. 4338.—Whereas it apears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Nanji Toponbhai and Company, Bazar Road, Cochin-2, Mattanchery Village, Cochin Taluk, Ernakulam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35019/388/76-PF. II]

का० आ० 4339.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जावरी लाल एण्ड संस, बाजार रोड कोचिन, मट्टनचेरी गाँव, कोचीन तालुका, एर्नाकुलम जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(389)/76-पी०एफ-2]

S.O. 4339.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Javerilal and Sons, Bazar Road, Cochin-2, Mattancherry Village, Cochin Taluk Ernakulam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1976.

[No. S. 35019/389/76-PF. II]

का० आ० 4340.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि माडर्न डाईंग वर्क्स डिन्डिगल रोड, कारूर त्रिची जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(390)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 4340.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Modern Dyeing Works, Dindigul Road, Karur, Trichy District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019/390/76-PF. II]

का० आ० 4341.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स वैस्टर्न एजेन्सीस, एनोक चैम्बर, चैम्बर, चिन्नाकडा-क्वीलन, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(391)/76-पी० एफ-2]

S.O. 4341.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Western Agencies, Enoch Chamber, Chinnakkada, Quilon, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1962), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1976.

[No. S. 35019/391/76-PF. II]

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4342.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स अनिल वीविंग वर्क्स मानी बेगमवाडी, सलावतपुरा, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(383)/76-पी० एफ-2]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

New Delhi, the 28th October, 1976

S.O. 4342.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anil Weaving Works, Nani Begamwadi, Salabatpura, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35019(383)/76.-PF. II]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1976

का० आ० 4343.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राऊरकेला स्टील प्लांट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी डा० बी० एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राऊरकेला स्टील प्लांट के प्रबन्धतंत्र की बारासुआ लोह अयस्क खानों में नियोजित निम्नलिखित कर्मकारों पर दंड अधिरोपित करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ?

कर्मकारों के नाम	लगाया गया दंड
1. श्री एन० अप्पाराव, डम्पर प्रचालक	9-7-75 से 1-7-76 को अगली वेतनवृद्धियों के देय होने तक वेतनमान में 510 रु० पर वेतन की कटौती।
2. श्री एस० के० डे०, अभिलेखक	कुल वेतनमान में वेतन की 25-5-75 से निचले स्तर तक कटौती।
3. श्री ए० के० चौधरी, अयस्क हैंडलिंग संयंत्र परिचर	1-7-76 और 1-7-77 को देय वेतनवृद्धि को संचयी प्रभाव से रोकना।
4. श्री के० एस० नायर, ज्येष्ठ भंडारी	1-7-76 को देय वेतनवृद्धि को संचयी प्रभाव से तीन वर्ष के लिए रोकना।
5. श्री जी० एस० टंडन, ज्येष्ठ शॉवेल प्रचालक	1-7-75 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि को संचयी प्रभाव से तीन वर्षों के लिए रोकना।

यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल-26012(3)/76-डी-4(बी)]

भूपेन्द्र नाथ, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1976

S.O. 4343.— Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Rourkela Steel Plant of Messrs Hindustan Steel Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Dr. B.N. Misra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

THE SCHEDULE

Whether the action of the management of Rourkela Steel Plant of Messrs Hindustan Steel Limited in Imposing punishments on the following workmen employed at Barsua Iron Ore Mines was justified:—

Names of the workmen	Punishments imposed
1. Shri N. Apparao, Dumper Operator	Reduction of pay with effect from 9-7-75 at Rs. 510/- in the scale till the next increments fell due on 1-7-76.
2. Shri S.K. Dey, Recorder	Reduction of pay to lower stage in the time scale with effect from 25-5-75.
3. Shri A.K. Choudhury, Ore Handling Plant Attendant	Stoppage of increment due on 1-7-76 and 1-7-77 with cumulative effect.
4. Shri K.S. Nair, Sr. Store Keeper	Stoppage of increment due on 1-7-76 for three years with cumulative effect.
5. Shri G.S. Tandon, Sr. Shovel operator	Stoppage of annual increment due on 1-7-75 for three years with cumulative effect.

If not, to what relief are the concerned workmen entitled?

[No. L-26012(3)/76-D-IV (B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer.

New Delhi, the 29th October, 1976

S.O. 4344.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bhubaneswar in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Kalta Iron Ore Mines of Messrs. Hindustan Steel Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 26th October, 1976.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

PRESENT :

Dr. B. N. Misra, LL.M. (London), Ph.D. (London), Bar-at-law Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 7 (Central) of 1975

Bhubaneswar, the 14th October, 1976

BETWEEN

The employers in relation to the management of Kalta Iron Ore Mines, Hindustan Steel Limited. .. First party

AND

Their workmen .. Second party

APPEARANCES :

Sri B. B. Rath, Advocate ... For the first party

None for the second-party.

AWARD

In exercise of the powers conferred by section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication, vide Order No. L. 2611/3/75/DIV/(B) dated 4-10-75 :—

"Whether the existing rates of wages payable to the piece-rated miners recruited by Messrs. Hindustan Steel Limited through Central Labour Depot, Gorakhpur, and employed at their Kalta Iron Ore Mines, Post Office Kalta are adequate ? If not, to what relief are the said Minor entitled ?"

2. As per the terms of reference, the aforesaid industrial dispute is said to exist between the employers in relation to the management of Kalta Iron Ore Mines, Hindustan Steel Limited and their workmen.

3. After registration of the reference the management appeared and filed its written-statement. The workmen also appeared through the Vice-President and General Secretary of the North Orissa Workers' Union and filed their written-statement. In its additional written-statement the management contended that the present reference regarding adequacy or otherwise of the existing rates of wages had never been raised as a demand by the workmen before the management and as such the present reference was not competent. After hearing both sides it was decided that the question of maintainability of the present reference in view of the aforesaid ground taken by the management should be taken up for hearing as a preliminary issue. The case was called on for hearing on the preliminary issue on 14-9-76. The management appeared but the workmen and their Union representatives remained absent inspite of notice. The hearing was taken up and one witness was examined on behalf of the management. Arguments for the management were also heard in full.

3. M.W. 1 is working in the Personal Department of the management-Company and he looks after the Mines Department. He has stated that the present reference is whether the existing rates of wages of the piece-rated miners recruited by the management through the Central Labour Depot, Gorakhpur and employed at the Kalta Iron Ore Mines of the management are adequate. The present reference has been made by the Central Government after the Assistant Labour Commissioner (Central), Rourkela submitted his conciliation failure report. Ext. 1 is the true copy of the said conciliation failure report. Prior to conciliation the North Orissa Workers' Union had sent Letter No. IM/KIH/13/74/206-207 dated 1-6-74 to the management. Ext. 2 is the certified copy of the aforesaid letter submitted by the Union on behalf of the workmen. M.W. 1 has stated that besides Ext. 2 no other letter or demand was sent or made by the Union regarding the wages of the piece-rated miners forming the subject-matter of the present reference. The Union had sent a separate letter to the Assistant Labour Commissioner (Central), Rourkela in respect of the implementation of the Steel Wage Board Award for Gorakhpur labour engaged at Kalta Iron Ore Mines of the management, vide letter No. IM/KIH/4/75/55 dated 16-4-75. Ext. 3 is a true copy of that letter and along with it the Union had enclosed a statement of demand. Ext. 3/1 is the true copy of the statement of demand enclosed by the Union along with Ext. 3. According to M.W. 1, the matters referred to by the Union in Exts. 3 and 3/1 were never brought to the notice of the management by way of demand on behalf of the workmen prior to conciliation. Ext. 2 contains the only demand which had been raised by the Union on behalf of the workmen before the management. In Ext. 2 the only demand made by the Union was for enhancement of the wage-rates as per the memorandum of settlement signed between the Union and the management and it has nothing to do with the piece-rated miners recruited through the Central Labour Depot, Gorakhpur and with the subject-matter of the present reference. M.W. 1 has explained that the settlement between the Union and the management referred to in Ext. 2 relates to the wages of the piece-rated miners recruited directly by the management itself and that settlement is in no way concerned with the wages of the piece-rated miners recruited through the Central Labour Depot, Gorakhpur and that the demand as per Ext. 2 was for enhancement of wages only on the basis of the memorandum of settlement. To a query from the Tribunal, M.W. 1 replied that in Exts. 3 and 3/1 the demand of the Union relates to the wages of the piece-rated miners recruited through the Central Labour Depot, Gorakhpur. M.W. 1 added that as he had already explained, the said demand had not been raised by the Union before the management prior to conciliation. The demand of the Union as per Exts. 3 and 3/1 came to the knowledge and notice of the management for the first time during conciliation.

5. The above evidence of M.W. 1 has not been challenged. The evidence of M.W. 1 is fully corroborated by the documentary evidence filed on behalf of the management. It is seen that Ext. 2 was the demand dated 1-6-74 which was submitted by the Union on behalf of the workmen to the management. In Ext. 2 the demand is—".....kindly enhance the wage rates as per the memorandum of settlement signed between us and the Principal employer M/s Hindustan Steel Limited,.....". In Ext. 2 there is absolutely no demand on behalf of the workmen for upward revision of the wages payable to the piece rated miners a recruited by M/s Hindustan Steel Limited through Central Labour Depot, Gorakhpur and employed at the Kalta Iron Ore Mines on the ground that the existing wages were inadequate. Ext. 3/1, which is the statement of demand submitted by the Union, has been appended to their letter dated 16-4-75, Ext. 3 which is addressed to the Assistant Labour Commissioner (Central), Rourkela. In Ext. 3/1 reference has been made regarding the wages of the labourers recruited through the Central Labour Depot which according to the Union, were less than the wages of the labourers directly recruited and doing similar work. M.W. 1 has admitted that the present dispute referred to the Tribunal by the Central Government relates to the demand of the Union as contained in Ext. 3/1, but he has clearly stated that besides Ext. 2, no other demand was made by the Union or the workmen before the management prior to conciliation. He has further stated that the demand or the Union as per Exts. 3 and 3/1 came to the knowledge and notice of the management for the first time during conciliation. Thus, there can be no doubt that the present dispute, as per the terms of the reference, relating to the adequacy or otherwise of the wages of the piece-rated miners recruited by the management through the Central Labour Depot, Gorakhpur, had never been raised by the workmen or the Union with the management prior to conciliation.

6. In A.I.R. 1968 S. C. 529 the Supreme Court inter-alia held :

"....Thus, both the respondents, in their claims put forward before the management of the appellant, requested for payment of retrenchment compensation and did not raise any dispute for reinstatement. Since no such dispute about reinstatement was raised by either of the respondents before the management of the appellant, it is clear that the State Government was not competent to refer a question of reinstatement as an industrial dispute for adjudication by the Tribunal. The dispute that the State Government could have referred competently was the dispute relating to payment of retrenchment compensation by the appellant to respondent No. 3 which had been refused. No doubt, the order of

the State Government making the reference mentions that the Government had considered the report submitted by the Conciliation Officer under sub-section (4) of Section 12 of the Industrial Disputes Act, in respect of the dispute between the appellant and workman employed under it, over the demand mentioned in the Schedule appended to that order; and, in the Schedule, the Government mentioned that the dispute was that of reinstatement of respondent No. 3 in the service of the appellant and payment of his wages from 21st February, 1958. It was urged by Mr. Gopalakrishnan on behalf of the respondents that this court cannot examine whether the Government, in forming its opinion that in industrial dispute exists, came to its view correctly or incorrectly on the material before it. This proposition is, no doubt, correct; but the aspect that is being examined is entirely different. It may be that the Conciliation Officer reported to the Government that an industrial dispute did exist relating to the reinstatement of respondent No. 3 and payment of wages to him from 21st February, 1958, but when the dispute came up for adjudication before the Tribunal, the evidence produced clearly showed that no such dispute had even been raised by either respondent with the management of the appellant. If no dispute at all was raised by respondents with the management, any request sent by them to the Government would only be a demand by them and not an industrial dispute between them and their employer. An industrial dispute, as defined, must be a dispute between employers and employers, employers and workmen, and workmen and workmen. A mere demand to a Government, without a dispute being raised by the workmen with their employer, cannot become an industrial dispute. Consequently, the material before the Tribunal clearly showed that no such industrial dispute, as was purported to be referred by the State Government to the tribunal, had ever existed between the appellant Corporation and the respondents and the State Government, in making a reference, obviously committed an error in basing its opinion on material which was not relevant to the formation of opinion. The Government had to come to an opinion that an industrial dispute did exist and that opinion could only be formed on the basis that there was a dispute between the appellant and the respondents relating to reinstatement. Such material could not possibly exist when, as clearly as March and July, 1958, respondents No. 3 and respondent No. 2 respectively had confined their demands to the management to retrenchment compensation only and did not make any demand for reinstatement. On these facts, it is clear that the reference made by the Government was not competent. The only reference that the Government could have made had to be related to payment of retrenchment compensation which was the only subject-matter of dispute between the appellant and the respondents."

7. In the present case, as already noted, the only demand which the Union had raised on behalf of the workmen prior to conciliation was for enhancement of the wage-rates of the workers engaged in the Kala Iron Ore Mines as per the memorandum of settlement signed between the Union and the management. It is worthy of note that in Ext. 2 there is no mention of the piece-rated miners recruited through the Central Labour Depot, Gorakhpur. Accordingly, it must be held that the present dispute which has been referred for adjudication had never been raised by the workmen before the management prior to conciliation. Therefore, for the same reasons as stated in A.I.R. 1968 S. C. 529, the present reference made by the Central Government is incompetent and not maintainable.

8. Award is passed accordingly.

Sd/-
B. N. MISRA
14-10-76
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Bhubaneswar.

Dated 14-10-76

[No. L-26011(30)/75-D-IV(B)]
BHUPENDRA NATH, Desk Officer

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1976

का० आ० 4345.—केन्द्रीय सरकार, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1948 के नियम 3 के साथ पठित अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गिरधारी लाल व्यास को, राजस्थान राज्य के लिए सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करती है, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 40 तारीख 4/27 दिसम्बर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 7 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री गिरधारी लाल व्यास,
अध्यक्ष,
खान मजदूर कांग्रेस-भीलवाड़ा
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी
जयपुर"

[फा० सं० यू-18012/4/75-एम 3]
सी० आर० निम, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 1976

S.O. 4345.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) read with rule 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules 1948, the Central Government hereby appoints Sri Girdhari Lal Vyas to be a member of the Advisory Committee for State of Rajasthan and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 40 dated the 4th/27th December, 1973, namely :—

In the said notification, for the entry against Serial No. 7, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Girdhari Lal Vyas,
President,
Khan Mazdoor Congress—Bhilwara,
C/o Rajasthan Pradesh Congress Committee,
Jaipur."

[File No. U-18012/4/75-MIII]
C. R. NIM, Under Secy.

New Delhi, the 25th October, 1976

S.O. 4346.—In pursuance of the section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Shri Ramkishan Verma, owner Alughata Sand Stone Mines and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd October, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M. P.)

Case No. CGIT/LC(R)(32) of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shri Ramkishan Verma son of Shri Narsinghlal Koli, Resident Jalwara, Tehsil Kishenganj, District Kota, Owner Alughata Sand Stone Mines and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—None

For workmen—Shri M. P. Sharma, President.

AWARD

Jabalpur, the 25th September, 1976

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide its Order No. L-29011/24/75-D.O.-3(B) dated 12th May, 1975, projecting the following dispute for adjudication :—

"Whether the action of Shri Ram Kishen Verma, son of Shri Narasing Lal, Resident of Jalwara, Tehsil Kishenganj in the District of Kota in terminating the services of Shri Dhannalal Verma, Stone Cutter in Alughata Sand Stone Mines, Tehsil Kishanganj, District Kota with effect from the 20th July, 1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?".

2. The case of the Union is that Dhanna Lal Verma Stone Cutter was made to sit idle with effect from 20th July, 1974 by the employer without giving him prior notice or retrenchment compensation and without levelling any charge against him for any misconduct etc. The Union took up the matter with the employer by registered notice Ex. M/1 and getting no response it raised the dispute before the Assistant Labour Commissioner (Central) vide Ex. M/3. The employer has not taken care to appear before this Tribunal even after proper service. As per statement of Shri M. P. Sharma, President of the Union, this employee was earning about Rs. 10/- per day. The Union leader raised a dispute with the employer by writing a registered letter copy of which is Ex. M/1. That letter has reached the employer as is clear from the acknowledgement Ex. M/2 filed by Shri M. P. Sharma. When the employer did not respond to the demand the dispute was raised before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota. The employer did not turn up and therefore the settlement could not be arrived at.

3. This Tribunal also made attempts to serve the employer but the employer did not care to appear or submit the written statement even. The case proceeded exparte. The Union President, Shri M. P. Sharma, has proved the case of the workman by his own statement on oath. The concerned workman is, therefore, declared to be continuing in the employment of the employer as the termination of his services was bad in law. Dhannalal Verma had been earning his wages elsewhere during this period, hence back wages are not allowed. Within one month from the date of publication of this award the employee shall report to the employer for duty and from that date onward he will be entitled to wages at the rate of Rs. 10/- per day if the employer fails to give him suitable employment. The employer shall pay Rs. 100/- towards costs of litigation to the concerned Union. Award is given accordingly.

Dated 25-9-1976 S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L-29011/24/75-DO III-B]

S.O. 4347.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Shri Prabhulal Anthalal, Mine Owner, P.O. Karauli, Distt. Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd October, 1976.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(3) of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shri Prabhulal Anthalal, Mine Owner, ost Office, Karauli (District Sawaimadhopur) and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—None.

For workmen—Shri M. P. Sharma, President.

DISTRICT : Sawaimadhopur (Rajasthan). INDUSTRY : Stone Mine

AWARD

Jabalpur, the 25th September, 1976

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide its Order No. L-29011/62/74-LRIV Dated 18th January, 1975 projecting the following dispute for adjudication :—

"Whether the demand of workmen employed in Langra and other Sand Stone Mines of Group 10 of Shri Prabhulal Anthalal of Tehsil Karauli, District Sawaimadhopur for the payment of Bonus @ 20 per cent for the accouting years 1967-68 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72 and 1972-73 is justified? If not, to what quantum and Bonus are the workmen entitled for each of these years?"

2. The case of the Union is that the employer of these Stone Mines has not paid profit sharing bonus to the workmen since 1967 to 1973 even though he has made huge profits. 20 per cent bonus is therefore claimed for this period. Notice was given to the employer raising the dispute and after receiving no response the Union took up the matter before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota. The employer did not turn up during the course of conciliation proceedings. The employer has not turned up before this Tribunal as well and ultimetely service had to be effected by publication in the newspapers.

3. The Union President has filed a printed rate list applicable from 1-10-1974 and published by the Mining Lease Holders Association, Kota. He has stated on oath that ordinarily the production costs is Rs.48/- per 100 Sq.Ft. while according to the rate list the minimum price is Rs. 55/- per 100 Sq.Ft. of the red stone which is produced in this mine. Thus there is an apparent profit margin of at least Rs. 7/- per hundred Sq.Ft. extracted stone. There is nothing to rebut this evidence. Of course, the calculations are based on surmise drawn from prevailing rates but there

seems to be no way out when the employer refuses to cooperate. There is thus sufficient profit entitling the workmen to receive profit sharing bonus form the employer.

4. It is, therefore, held that all those employees we have worked for more than 30 days in any accounting year in dispute in these establishments shall be entitled to minimum bonus as laid down in Sec.10 of the payment of Bonus Act during the said accounting years beginning from 1967-68 to 1972-73. The employer shall further pay Rs.100/- as costs to the Union which has been compelled to spend on this litigation due to the non-cooperative attitude of the employer. Awarrd is given accordingly.

Dated 25-9-1976 S. N. JOHARI, Presiding Officer

[No. L-29011/62/74-LR IV]

S.O. 4348.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Shri Shiv Shankar Agarwal, Mine Owner, Near Multipurpose Secondary School, Gumanpura, Kota and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd October, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(52) of 1975.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shri Shiv Shankar Agarwal, Mine Owner, Near Multipurpose Secondry School, Gumanpura, Kota and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—None.

For workmen—Shri M. P. Sharma, President of the Union.

INDUSTRY : Stone mine DISTRICT : Kota (Rajasthan)

AWARD

Jabalpur, the 25th September, 1976

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide its order No. L-29011/104/75/DOIIIB. dated 23rd August, 1975 projecting the following dispute for adjudication :—

"Whether the action of Shri Shiv Shankar Agarwal, Mine Owner, Near Multipurpose Higher Secondary School, Gumanpura, Kota in terminating the services of Shri Marumathi, son of Shri Raju, Stone Cutter, Rangwari Masonary Sand Stone Mines, Kota with effect from 28th January, 1975 is justified ? If not, to what relief the workmen is entitled to ?"

2. The case of the Union is that Marumathi was a Stone Cutter employed in the said mine, without prior notice and without payment of retrenchment compensaion etc. he was stopped being given work from 28th January, 1975. His past wages amounting to Rs. 219.30 were also not paid by the employer. He was earning about Rs. 10 per day. As a piece rated worker he was getting Rs. 34 per truck Chingari Stone and Rs. 24 per truck Rubbal stone. Besides that he was getting Rs. 140 per Cft. for digging holes or blasting. The Union leader raised a dispute with the employer by writing a registered letter, copy of which is exhibited as Ex. M/1. That letter had reached the employer as is clear from the acknowledgement Ex. M/2 filed by Mr. Sharma. When the employer did not respond to the demand the dispute was raised before the Asstt. Labour Commissioner (Central) Kota. The employer did not turn up and therefore the settlement could not be arrived at.

3. This Tribunal also made attempts to serve the employer and ultimately service had to be effected by publication in the newspaper. The Union President has proved the case of the workman by his own statement on oath. The concerned workman is, therefore, declared to be continuing in the employment of the employer as the termination of his service was bad in law. He had been earning his wages elsewhere during this period, hence back wages are not alowed except that the employer shall pay Rs. 219.30 to the workman as the dues of his past wages, within one month from the date of publication of this award the employee shall report to the employer for duty and from that date onward he will be entitled to wages at the rate of Rs. 10 per day if the employer fails to give him suitable employement. The employer shall further pay Rs. 100 towards costs of litigation to the concerned Union. Award is given accordingly.

Dated : 25-9-1976 S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L 29011/104/75-DO. III(B)]

S.O. 4349.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Shri Sant Ram, Mine Owner, Village and Post Offiie Dhakad Khedi, Kota and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd October, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(62) of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shri Sant Ram, Mine Owner, Village and Post Office Dhakad Khedi, Kota and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—None.

For workmen—Shri M. P. Sharma, President of the Union.

INDUSTRY : Stone Mine—DISTRICT : Kota (Rajasthan)

AWARD

Jabalpur, the 25th September, 1976

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide its Order No. L-29011 (115)/75-D. III(B) Dated 25th November, 1976 projecting the following dispute for adjudication :—

"Whether the action of the management of Masonary Stone Mine, Tanki Area of Shri Sant Ram Mine Owner resident of Village and Post Office Dhakadkheri, Kota in terminating the services of Shri Mustafa Khan, Stone Cutter with effect from the 25-4-1975 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The case of the Union is that Mustafa Khan was working as a Stone Cutter when from 25th April 1975 he was made to sit idle without prior notice and without payment of any retrenchment compensation. A demand was raised with the employer by a notice dated 14-5-1975, copy of which is Ex. M/1. That was personally served on the employer vide acknowledgement Ex.M/2. When it went unheeded the dispute was raised before the Asstt. Labour Commissioner (Central) Kota but the employer did not attend, hence no settlement could be arrived at.

3. Mustafa Khan has sent a letter dated 25th April, 1975 which states that he has received Rs. 254 the arrears of

wages and he does not want to press the claim further. No settlement has been filed before this Tribunal. The Union President states that he was not taken into confidence. The workman has not cared to attend.

4. As the workman seems to be satisfied after receiving the amount of Rs. 254 it is no use pressing the dispute further, hence no dispute award is given in the present case. However, the Union has been put to all the expenses because of the non-cooperative attitude of the employer hence the employer shall pay Rs. 100 towards the costs of litigation to the Union. Award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L-29011/115/75-DO. III B]

25-9-1976.

New Delhi, the 27th October, 1976

S.O. 4350.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 at Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Messrs N. P. Sharaf, contractors, Chiriburu Quartzite Mine of Messrs Orissa Cement Limited, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th October, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 5 of 1974

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

(Ministry's order No. L-29011(69)/73-LR. IV(ii) dated 4-1-74.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Orissa Cement Limited, Calcutta and Messrs N. P. Sharaf, Contractors, Chiriburu Quartzite Mine of Messrs Orissa Cement Limited, Calcutta.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Messrs Orissa Cement Limited.—Shri V. K. Agarwal, Assistant Secretary.

On behalf of Messrs N. P. Sharaf, Contractors.—Shri S. C. Jain, Labour Adviser.

On behalf of the workmen.—Shri Lalit Burman, Authorised representative of the workmen.

STATE : Bihar INDUSTRY : Quartzite Mine

AWARD

Dhanbad, the 29th September, 1976

The Government of India, Ministry of Labour, sent the above reference to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed :

SCHEDULE

1. Whether the action of the management of Messrs Orissa Cement Limited, Calcutta and N. P. Sharaf Contractors at Chiriburu Quartzite mine of Messrs Orissa Cement Limited in refusing employment, with effect from the 29th September, 1973, to 1100 workmen employed by them was justified?

2. Whether the workmen of the said employers are entitled to bonus at the rate of 20 per cent of their wages for the accounting year ended on the 31st December, 1972 ?

3. Whether the demand of the workmen of the said employers for revision of wage structure is justified? If so, to what relief are the workmen entitled?

On receipt of the above reference notices were issued and served on both sides. Parties filed their respective written statements and took other steps. The case proceeded along its course and ultimately I fixed the case on 30-8-76 for evidence and argument on preliminary point. On 30-8-76 both parties appeared and submitted before me with a petition that all the outstanding disputes between the workmen and their present employers have been settled amicably and mutually out of court and that in view of the above facts the parties do not wish to proceed any further in the matter. Since no industrial dispute between the parties any more exists, I have no other option than to pass a 'No dispute' award in this case.

In the circumstances I make a 'No dispute' award in respect of the industrial dispute involved in this reference.

This is my award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

[No. L-29011(69)/73-LR IV]

D. D. CHAUFLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4351.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 531, तारीख 2 मार्च, 1961 में 5 जुलाई, 1976 के अपराह्न से और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(35) श्री सी० एम० देवस्थाले"

[फा० संख्या ए-35017/1/75-एम-1]

जे० सी० सक्सेना, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 1976

S.O. 4351.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952, (35 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 531 dated the 2nd March, 1961, with effect from the after-noon of the 5th July, 1976, namely :—

In the said notification, the following entry shall be omitted, namely :—

"(35). Shri C. M. Deosthale".

[F. No. A-35017/1/75-MI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

S.O. 4352.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sree Lakhimata Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th October, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 17 of 1974

(Ministry's Order No. L-2012/35/74-LRII, dated, nil, 1974).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Srec Lakhimata Colliery of Messrs Coal Mine Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad.

AND

Thier Workmen

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen.—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 22nd October, 1976

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Sree Lakhimata Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachattil District Dhanbad in stoppoing Shri Dilip Kumar Gorai, Clerk from work with effect from March, 1973 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. Usual notices were issued on the receipt of the reference, and in response to that, Shri Dilip Kumar Gorai and M/s. Eastern Coalfields Liimted (Successors-in-interest of M/s. Coal Mines Authority Limited) submitted their written statements.

3. The case of Shri Dilip Kumar Gorai is that he was appointed as a Grade III Clerk on a monthly basic salary of Rs. 180 and usual D. A. by M/s. J. K. Gorai and Company (the old owners of the Lakhimata Colliery) on August 23, 1972 and he joined his duty on August 25, 1972 as an Attendance Clerk. The management of the colliery was taken over by the Coal Mines Authority Limited with effect from 31-1-1973 under the Coal Mines (Taking Over of Management) Ordinance, 1973. He was, stopped from working in the colliery with effect from March 3, 1973 in a highly illegal and arbitrary manner. He has, therefore, prayed that he should be reinstated with full back wages and other benefits. On the other hand, M/s. Eastern Coalfields Limited have travesed the pleadings of Sri Gorai and have averred that the reference is bad in as much as Shri Goari did not raise any industrial dispute with them; it is also bad because under the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 no award can be passed or enforced against them; that on the promulgation of the Ordinance, a large number of persons manipulated colliery records with the help and connivance of the erstwhile owners of the colliery and get their names entered in the rolls of the colliery and Shri Gorai was one of such un-authorised entrants in service; that, on a serutiny of facts, however, it was discovered that Sri Gorai was not a workman but an un-authorised inductee, and, therefore, his services were terminated.

4. After filing the written statement, Sri Gorai did not put in appearance on June 26, 1976. Fresh notice was issued to him for appearance on August 6, 1976. He appeared on that date and stated that he will not file any rejoinder to the written statement filed by M/s. Eastern Coalfields Limited. On that date, it appeared necessary to issue notice to M/s. J. K. Gorai and Company also, the old owners of the mine, so that the matter may be adjudicated finally between all the three parties. The case was taken up on August 30, 1976 but neither Sri Gorai appeared nor did M/s. J. K. Gorai and Company put in appearance. The case was, therefore, adjourned to October 21, 1976 and fresh notices were issued but with the exception of M/S. Eastern Coalfields Limited. Sri Gorai and M/s. J. K. Gorai and Company were again absent. The burden to prove that Sri Gorai was really a workman appointed in a lawful manner and was not an intruder lay upon him but inspite of several adjournments given to him to prove his case, he has chosen to remain absent and, therefore, no relief can be awarded to him in the absence of proof of entitlement to any relief.

5. My award is that Sri Dilip Kumar Gorai is not entitled to re-instatement or to back wages or to any other relief.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-20010/35/74-LR. III/D III (A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 1st November, 1976

S.O. 4353.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the South Indian Bank Limited Trichur and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th October, 1976.

BEFORE THIRU T. N. SINGARAVELU, B.A., B.L.,

INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Industrial Dispute No. 34 of 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of South Indian Bank Limited, Head Office Trichur-1, Kerala).

BETWEEN

The workman represented by.—The General Secretary, South Indian Bank Employees Association, Post Office Road, Trichur-1 (Kerala).

AND

The Chairman, South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur-1, Kerala.

REFERENCE :

Order No. L. 12011/4/75/DII/A, dated 15th May, 1975 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Friday, the 8th day of October, 1976 upon persuing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record, and upon hearing the arguments of Thiru R. Jamal Nazeem for Thiruvalargal Aiyer & Dolia, advocates appearing for the workmen and of Thiru M. Venugopalan, Advocate appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :—

AWARD

Friday, the 15th day of October, 1976

This is an Industrial Dispute between the South Indian Bank Limited, Trichur and its employees with reference to the transfer of 74 workers. This dispute has been referred to this Tribunal by the Government of India in its Order No. L-12011/4/75/DII/A, dated 15th May, 1975 of the Ministry of Labour.

2. The issue referred by the Government runs thus :

Whether the Management of the South Indian Bank Limited, Trichur was justified in transferring the following employees of the Bank during the period of agitation of the employees in 1973. If not, to what relief are these employees entitled ?

1. K. P. Jose
2. C. I. George
3. N. D. Paulson
4. P. A. Chakkunny
5. C. L. Anthony
6. A. V. Francis
7. V. G. Antony
8. K. P. Jose
9. K. V. Jhon
10. M. V. Joseph
11. Jhon C. Andrews
12. Thamby Paul
13. Varghese Paul K.
14. Raphael Jacob
15. K. I. Kochappu
16. P. M. Inasu
17. C. V. David.
18. E. V. Davy
19. N. S. Varghese
20. P. P. Sukumaran
21. M. L. Antony
22. K. C. Paul
23. A. T. Jose
24. Antony Valapilla
25. K. O. Antony
26. P. D. Jose
27. P. I. Francis
28. A. P. Jose
29. T. R. Chacko
30. C. C. Aippunny
31. C. A. Sunny
32. P. R. C. Menon
33. K. K. Gopi
34. C. C. Joseph
35. K. P. Subramaniam
36. C. M. Jacob
37. K. Aravindhakshan
38. K. V. Antony
39. V. C. George
40. K. T. Joseph
41. K. C. Jacob
42. K. V. Mathai
43. M. Premachandran
44. K. T. Sivaraman
45. S. K. Irudayaraj
46. A. L. Joseph
47. T. P. Rangaswamy
48. Francis Jacob
49. M. Arumugam
50. K. C. Thomas
51. K. Kasi
52. P. J. John
53. V. O. Joseph
54. K. Doraivelu
55. N. V. Babu
56. P. J. Immanuel
57. P. V. Thomas
58. C. J. Joseph
59. K. S. Venugopalan
60. P. Sreekumaran
61. N. Rajendran
62. C. J. Raphael
63. M. P. Poulose
64. O. K. Perinchu
65. M. K. Devassy
66. Harold Chithayagam
67. P. K. Ranganathan
68. Jose C. George
69. K. N. Francis
70. T. T. Antony
71. K. A. George
72. T. C. Antony
73. K. C. Sethumadhavan
74. N. P. Devassy.

3. The claim Statement filed by the Central Secretary of the South Indian Bank Employees' Association, Trichur is briefly this : There was agitation and strike of the employees of the South Indian Bank Limited, Trichur during May-August, 1973 and, after the strike, the Management effected transfer of employees of about 82 persons in order to disrupt the Union and punish the employees for having taken part in the strike. The transfers were wholly motivated and were the result of the policy of victimisation adopted by the Management. Most of the persons were adversely affected by the transfers which was punitive in nature. Though the Settlement effected on 20-8-1973 provided for reconsideration of the transfers, most of the persons transferred received only unfavourable orders. Therefore, an Award should be passed cancelling these transfers and retransferring them to their original place.

4. The Management of South Indian Bank Limited, Trichur filed a Counter Statement as follows: It is totally wrong to state that the transfers were punitive or mala fide. No transfer was effected with the intention of harassing or punishing any employee. Of course, it is true that some employees were tranferred, but it is an ordinary incidence of employment. Further, in pursuance of a Settlement, the Management reviewed individual cases and passed favourable orders for many persons. The transfers were highly necessary and the right to transfer is a managerial right. That apart, the dispute regarding the tranfers was discussed and talked over, and a Settlement was arrived at on 20-8-1973 in the presence of the Honourable Chief Minister of Kerala. The said Settlement specifically provided for the filing of review applications by individuals (transferees) and the Management was to take appropriate decision on them. Accordingly, many cases were reviewed and therefore there is no dispute over the transfer after the Settlement dated 20-8-1973. As it is, there is no Industrial Dispute at all and the claim of the Union for cancellation of the transfer orders under the guise of a dispute is misconceived. In fact, the Union raised disputes with reference to two of its employees and they were referred to this Tribunal for disposal. They have been disposed of and therefore this reference itself is wrong and invalid.

5. Learned counsel for the Management raised a preliminary point that there is no Industrial Dispute after the Settlement dated 20-8-1973 and that the reference itself (after the Settlement) is incompetent. This question was taken up as a preliminary point by consent of both parties and learned counsel for both sides marked their documents and argued the matter on the preliminary point with reference to the validity or otherwise of the reference.

6. It is common ground that there was agitation and strike of the employees of the Bank during May-August, 1973 and that, during the agitation and strike, some employees were transferred from one place to another to meet the exigencies of the situation. Finally, at the instance of the Honourable Chief Minister of Kerala, an agreement was arrived at between the Management and the Bank Employees on 20-8-1973. Ex. M-1 is the certified copy of the said agreement and Clause (D) runs thus :

> "The General Secretary will be retransferred to Trichur. All other transfer orders will be reviewed, if after restoration of normal working conditions the employees apply individually for reconsidering the transfers within a month."

7. Learned counsel for the Management strenuously contends that the question of transfer of employees prior to the Settlement were fully discussed and settled between the parties under Ex. M-1. Accordingly, the General Secretary of the Union was retransferred to Trichur and it was agreed that all other transfer orders will be reviewed on applications by the individual employees within a month. It is therefore argued that the question of transfers was settled between parties on 20-8-1973, and since all the transfers in question were made prior to the said Settlement, there is no further dispute to be adjudicated upon and therefore the reference is bad. As against this, learned counsel for the Union would argue that the Management reviewed only certain cases of transfers on their applications and that they did not pass favourable orders in respect of all the transferees, and therefore, it is open to the Union to raise a dispute with reference to the transferees whose cases were not considered favourably.

8. Now, Clause D of Ex. M-1 is very clear and there is no ambiguity about it. Both the parties agreed in the presence of the Honourable Chief Minister of Kerala that all other transfer orders then that of the General Secretary will be reviewed on their individual applications within a month. It is not disputed that all the review applications given to the Management were considered on their individual merits and appropriate orders were passed. Therefore, this dispute regarding transfers was specifically provided for in the Settlement Ex. M-1 and suitable orders

have been passed on the review applications. The orders on review petitions cannot be classified as favourable or unfavourable and there is no provision in the Settlement itself in respect of cases where unfavourable orders were passed. The Union appears to have bargained for a review of the transfers on individual applications and it has been done by the Management and appropriate orders passed. Therefore, there is nothing left out with reference to these transfers of employees which were made prior to the agreement dated 20-8-1973. In other words, further adjudication on these transfers is not called for and the Settlement cannot be reopened, nor individual cases considered afresh by this Tribunal as an Industrial Dispute.

9. Another point in favour of the Management is this: The very same Union raised disputes in respect of two of its transferee-employees and they resulted in I.D. No. 33 of 1974 and I.D. No. 34 of 1974 which were referred by the Government of India to this Tribunal. It is significant to note that the Union did not think it fit to raise a dispute with reference to other transferees at that time. In those disputes, the General Secretary of the Union filed Claim Statements pleading victimisation of the two workers. The Management filed Counter Statements and when the matters came up for enquiry, the Union did not participate in the enquiry, and kept itself aloof. A learned predecessor of mine passed Awards in those two disputes on 22-1-1976 holding that there were no merits in the claim of the Union and that there was no violation of any of the terms of Settlement Ex. M-1. The two Awards were published and they have become final. The further point is that the employee concerned in I.D. No. 33 of 1974 is one of the 74 employees now concerned in this Industrial Dispute. Therefore, the Union is barred from raising this dispute once again at this distance of time.

10. Learned counsel for the Management argued that the right to transfer an employee is a managerial right and that it should not be easily interfered with. It is urged that in an institution like a Scheduled Bank having branches all over the country, transfer of the employees is inevitable on the ground of exigencies of service and that the transfer is an incidence of employment. It is well-settled law that the Tribunal will not interfere in domestic administration, unless the transfer is mala fide or amounts to colourable exercise of power. Of course, this is a question of fact and we cannot go into it while dealing with the preliminary issue. However, the general principles are that normally the transfers, unless they constitute clear victimisation, will not be interfered with. In this case, as already stated, the transfer was the subject of a Settlement and a remedy has already been provided for and individual cases have been reviewed on their own merits. For all these reasons, I am of opinion that there is no Industrial Dispute with reference to transfers after the Settlement Ex. M-1 dated 20-8-1973. The agreement has clearly provided for the filing of individual review applications and suitable orders have been passed thereon. Obviously, there could not have been any understanding between the parties regarding the result of the review applications to be filed at a later date. There is no provision in the agreement for a further review of the orders passed by the Management and therefore Ex. M-1 is a settlement binding upon both the parties. The result is the dispute stands settled and this reference itself is not competent.

11. Learned counsel for the Union contended that the Settlement Ex. M-1 is not valid in law in as much as it has not been communicated to the proper authorities as per the rules of the Industrial Disputes Act. This argument is not in good taste. The Settlement Ex. M-1 was arrived at in the immediate presence of the Honourable Chief Minister of Kerala and it was only on his intervention this dispute itself was settled. Therefore, it is too late in the day to contend that the Settlement itself is not in accordance with law in as much as the copies of the Settlement were not duly communicated to the authorities. In 1964-I-L.L.J.-351 (Supreme Court), it was held that such communication is only a formality and not a condition precedent. Noncompliance with a condition of such kind would amount not to an illegality but only an irregularity.

12. For all these reasons, I hold that there is no Industrial Dispute and that the reference itself is invalid in view of the Settlement between the parties daed 20-8-1973. The preliminary objection is upheld and an Award is passed rejecting the claim. No costs.

Dated, this 15th day of October, 1976.

Witnesses Examined

For both sides : Nil.

Documents Marked

For workman : Nil.

For Management :

Ex. M-1/20-8-73—Memorandum of agreement between the Management and the Union (copy).

Ex. M-2/21/1-76—Award in I. D. No. 33 of 1974 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Ex. M-3/22-1-76—Award in I. D. No. 34 of 1974 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Note : Parties are directed to take return of their documents within six months from the date of the award.

T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer

[F. No. L-12011/4/75-D. II A]

R. P. NARULA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.